साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली
वर्ष-28 अंक- 52 26 दिसं॰ 2021 - 01 जनवरी 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए
स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए आवश्यक है मतदाताओं का मुखर होना पृष्ठ-6
मानवाधिकार थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है पृष्ठ-7

चुनावी खर्च में हो रहे दिन प्रतिदिन बढ़ौतरी का

कौन है ज़िम्मेदार?

चुनाव आयोग, सरकार या राजनीतिक पार्टियां

चुनावी चर्ख का विषय बहुत अहम है जिस पर हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता का आधार है इसलिये आवश्यक है कि चुनावी खर्च पर नियंत्रण किया जाए।

भारत वर्ष एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की स्वस्थ बहाली के लिए स्वतंत्र चुनाव प्रणाली की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, इसके लिए लिए बाक़ायदा चुनाव आयोग का गठन किया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष में जब एक सत्तारुढ़ पार्टी का कार्यकाल समाप्त होता है तो अगले सेशन के लिए चुनाव कराना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है, कभी कभी पांच वर्ष से पूर्व ही असमय चुनाव कराने की नौबत आए तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इन चुनावों पर हर बार भारी भरकम खर्च होता है। चुनावी खर्च एक ऐसा मुद्दा है जिसमें निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल और भारत सरकार तीनों के ही अपने अपने दृष्टिकोण हैं। सैद्धांतिक रूप से यह माना गया है कि चुनाव में भागीदारी करने या निर्वाचित होने का अधिकार देश के हर नागरिक को है इसलिए सबको एक समान अवसर प्रदान करने के लिहाज़ से चुनाव संहिता के तहत उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की गई थी, ताकि ऐसान हो कि आर्थिक ताक़त के बूते अमीर वर्ग चुनाव जीत जाए और अपेक्षाकृत ग़रीब या सामान्य तबक़े का व्यक्ति इसमें पिछड़ जाए। केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने निर्वाचन नियम 1961 के प्रावधान-60 में संशोधन करते हुए चुनाव ख़र्च सीमा दस प्रतिशत इज़ाफा करने का फैसला किया हैं इसके पीछे कोरोना महामारी को कारण बताया गया है। इसके अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए अब ख़र्च की अधिकतम सीमा सत्तर लाखा से बढ़ाकर सतहत्तर लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख से बढ़ाकर 31 लाख 75 हज़ार रूपए की जा सकती है। इससे पहले फरवरी 2014 में चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई गई थी। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के फैसले पर अमल के लिए निर्वाचन आयोग ने कमेटी बनाई है।

निर्वाचन आयोग के चुनाव ख़र्च सीमा का अनुपालन कराने के लिए कई उपाय कर रखे हैं, जैसे कि ख़र्च की स्वीकार्य लागत को तय करना, ख़र्च पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुकित करना, उम्मीदवार के ख़र्च संबंधी रजिस्टर की जांच और पर्यवेक्षकों के आंकलन से उनकी तुलना, यहां तक कि उम्मीदवारों के प्रमुख चुनावी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करवाना आदि। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सारे उपायों के बावजूद चुनावों में ध न के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने या खर्च की असलियत का पता लगाने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। जैसे-जैसे धन खर्च के नियमन का प्रयास हुआ, वैसे-वैसे इन नियमों को अप्रभावी बनाने के लिए नए-नए तरीक़े भी खोज लिए गए। इसके लिए राजनीतिक दलों का आपसी सामंजस्य, पार्टियों का इस मुद्दे पर सुविधापूर्ण विरोध, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के साथ ही प्रशासनिक शिथिलता भी दोषी है। राजनीतिक दलों का तर्क होता है कि चुनावी खर्च की अब तक निर्धारित सीमा अव्यवहारिक है। उम्मीदवारों पर तय सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में उनका तर्क होता है कि यदि चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ा दिया जाए तो उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में झूठ नहीं बोलना पड़ेगा।

इसके बावजूद सच्चाई कुछ दूसरी है। आज़ादी के बाद भारत के लोकतंत्र पर धन का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। लोकतंत्र पर धन के प्रभाव को देखना हो तो कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। देश के पहले तीन लोकसभा चुनावों में सरकारी खर्च प्रति वर्ष लगभग दस करोड़ रुपए था। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में यह एक हज़ार चार सौ तिरासी करोड़ था, जो वर्ष 2014 में बढ़ कर ढाई गुने से भी ज़्यादा यानि तीन हज़ार आठ सौ सत्तर करोड़ रुपए हो गया। एक करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले सांसदों का प्रतिशत सन 2009 में 58 प्रतिशत, 2014 में बयासी प्रतिशत और 2019 में बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया। एक अन्य आंकड़े के अनुसार दोबारा निर्वाचित (2019) सांसदों की संपत्ति में उन्तालीस फीसदी की औसतन वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा पच्चीस लाख रुपए, 2011 में चालीस लाख रुपए और 2014 में सत्तर लाख रुपए कर दी गई थी। इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि अगर कोई सामान्य या निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जन सेवा के लिए राजनीति को माध्यम बनाना चाहे तो उसके निर्वाचित होने के आसार न के बराबर हैं।

राजनीतिक दलों के कोष एवं उनके वित्तीय स्रोतों के नियमन को लेकर कभी भी दरअसल गंभीर प्रयास किए ही नहीं गए। अगर हुए भी हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से या तो परिभाषित नहीं किया गया या उनमें ऐसी ख़ामियां छोड़ दी गई कि जिनका प्रयोग राजनीतिकों द्वारा आसानी से अपने अनुकूल किया जा सके। जैसे बीस हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के दान का विवरण देने के कानून से बचने के राजनीतिक दलों द्वारा अपने नब्बे प्रतिशत तक के चंदे को इस निर्धारित सीमा के भीतर बताया जाता रहा है। वर्ष 2003 में संसद द्वारा यह उपबंध किया गया था कि किसी प्रत्याशी के पक्ष में यदि कोई बड़ा नेता उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो उसे उस प्रत्याशी के निर्वाचन ख़र्च में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रत्याशी के अतिरिक्त उसके

बाक़ी पेज 03 पर

मॉबलिचिंग के विरुद्ध झारखंड विधानसभा के ज़रिए क़ानून पारित करना स्वागतयोग्य : मौलाना महमूद मदनी

जमीअत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मॉब लिचिंग को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा पारित क़ानून का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि क़ानून के ज़रिए सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बीच विश्वास पैदा होगा। इसके साथ ही आपसी सद्भाव और शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। जमीअत उलेमा-ए-हिन्द शुरू से ही इस तरह के क़ानून बनाने की मांग करती आ रही है। उन्होंने देश के अन्य राज्यो से भी आग्रह किया है कि वह भी प्रभावी कानून के माध्यम से इस तरह के जघन्य कृत्यों पर अंकुश लगाएं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि झारखंड में हाल ही में मॉब लिचिंग की कई घअनाएं हुई हैं। इसी तरह देश के दूसरे हिस्से भी इससे प्रभावित रहे हैं। अधिकतर ऐसी घटनाएं, मुसलमानों और दलितों के विरुद्ध होती हैं और फिर आक्रोशित और उपद्रवी भीड़ द्वारा वीडियो बनाकर इसका प्रसार भी किया जाता है ताकि डर का माहौल पैदा किया जाए। प्रभावित समुदाय के लोगों को लगता है कि उन्हें किसी भी समय और कहीं भी हिंसा का निशाना बनाया जा सकता है। मौलाना मदनी ने कहा कि कुछ विशेष समुदायों को निशाना बनाना देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का कारण बनता जा रहा है। मॉब लिचिंग के मामले को केवल भीड़ के संदर्भ में नहीं बल्कि पीड़ित के नज़रिए से भी देखना चाहिए कि उसको और उसके समुदाय को कितना अपमानित और असहाय होने का अहसास कराया जाता है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीअत उलेमा-ए-हिन्द इस्लामोफोबिया, घृणा और हिंसक भीड़ के हमले के ख़िलाफ देश के संविधान के दायरे में संघर्ष कर रही है और इसे देश की सुरक्षा और विकास के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानती है। उन्होंने कहा कि मॉबलिचिंग के ख़िलाफ़ जिन राज्यों में क़ानून बना है, उनको अपने क़ानून के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसमें विशेष रूप से पुलिस प्रशासन और सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया हो।

भारत-अफ़ग़ान : खुल गई राजनयिक खिड़की

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद वहां की त्रस्त जनता के लिए मेडिकल सप्लाई की पहली खेप भेज कर भारत ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। भारत ने संकट के समय अफ़ग़ानिस्तान के लोगों की मदद करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप मानवीय मदद उपलब्ध कराई है। इसी के माध्यम से भारत की यह इच्छा भी प्रकट हुई है कि भारत काबुल के राजनयिक दरवाज़े पर अपने क़दम रखना चाहता है। दस भारतीयों और 94 अफ़ग़ान नागरिकों को काबुल से दिल्ली लाने वाले विमान के ज़रिये मेडिकल सप्लाई वहां भेजी गई है। यह खेप विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी और काबुल स्थित इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय में दी जाएगी। तालिबान संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तक पहुंच को मजबती से नियंत्रित करता है, ऐसे में भारत पिछले कुछ माह से तालिबान के अधिकारियों के साथ सतर्कतापूर्वक पर्दे के पीछे बातचीत में शामिल हुआ। अगस्त में भारतीय दूत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान के दोहा कार्यालय के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की थी। तालिबान का नेतृत्व कर रहे शेर मोहम्मद स्टेनकजई कर रहे हैं। स्टेनकजई ने भारत में ही शिक्षा ग्रहण की है।

1.6 मीट्रिक टन स्वास्थ्य सामग्री पहुंचते ही अफ़ग़ानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से मिली मदद का स्वागत किया और लेकिन कहा कि वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए उन्हें और मदद की ज़रूरत है। भारत इसके अलावा 5 लाख कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोज और 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं भेजने को भी तैयार है। अगर पाकिस्तान सड़क मार्ग के ज़रिये गेहूं भेजने में अडंगा न लगाता तो गेंहू कब का अफ़ग़ानिस्तान पहुंच चुका होता। पाकिस्तान के साथ भारत गेहूं की खेप के परिवहन के लिए नियमों को अन्तिम रूप देने की बातचीत करर हा है।

मानवीय आधार पर सहायता भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के अनुरूप दी है। वसुधैव कुटुम्बकम सनातन धर्म का मूल संस्कार है जो महाउपनिषदों सहित कई ग्रंथों में

बाक़ी पेज 11 पर

तालिबान : महिलाओं की शिक्षा और नौकरियों पर नरम रुख़

अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्तकी ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान का नया शासक तालिबान, महिलाओं तथा लड़कियों की शिक्षा तथा नौकरियों के लिए सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध है। साथ ही, उन्होंने देश के लाखों लोगों की जरूरत की इस घड़ी में मदद करने के लिए दुनिया से 'दया एवं सहानुभूति' दिखाने की अपील की है। मुत्तकी ने 'एसोसिएटेड प्रेस' से कहा कि तालिबान सरकार सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती है और अमेरिका से उसे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अमेरिका और अन्य देशों से 10 अरब डॉलर की उस राशि को जारी करने की अपील की, जिस पर 15 अगस्त को तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान को अपने कब्ज़े में लेने के बाद देश में तेजी से सैन्य हमले बढ़ने और अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति अशरफ ग़नी के अचानक, गुप्त रूप से देश छोड़ देने के बाद रोक लगा दी गई थी। मुत्तकी ने माना कि तालिबान द्वारा लड़कियों की शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं पर थोपी गई पाबंदियों को लेकर दुनिया में आक्रोश है। अफ़ग़ानिस्तान के कई हिस्सों में, तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सातवीं से 12वीं कक्षा की उच्च विद्यालय की छात्राओं को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है और कई महिला सिविल सेवकों को भी घर पर रहने का फरमान सुनाया गया। तालिबान अधिकारियों ने कहा कि उन्हें स्कूलों और कार्यस्थलों पर महिला तथा पुरुष के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने के लिए समय चाहिए, जो इस्लाम की उनकी गंभीर व्याख्या के अनुरूप है। मुत्तकी ने हालांकि कहा कि तालिबान अब बदल गया है उन्होंने कहा, 'देश के साथ और विश्व के साथ बातचीत कर हमने प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से प्रगति की है। हर गुज़रते दिन के साथ हम और अनुभव हासिल करेंगे और अधिक प्रगति करेंगे।

वर्ष 2021 में कोरोना ने निकाला स्वास्थ्य सुविधाओं का दम

राजधानी दिल्ली में लोग इस वर्ष कोरोना म्यूकोरमाइकोसिस व डेंगू जैसी घातक बीमारियों से जूझते रहे। वर्ष की शुरुआत में वैश्विक महामारी कोरोना से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अप्रैल व मई में कोरोना के डेल्टा वैरियंट के क़हर ने हर घर में लोगों के आंखों में आंसू ला दिया। आठ लाख से अधिक लोग बीमार हुए, जिसमें से 14,465 लोग असमय मौत के शिकार हुए। कोरोना के बढ़ते मरीज़ों के सामने स्वास्थ्य सुविधाओं ने घुटने टेक दिए थे। इस दौरान अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की कमी से लाचार मरीज़ और तीमारदार मदद के लिए गुहार लगाते रहे। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसने अपने परिजन, दोस्त, रिश्तेदार या परिचित के लिए इस स्थिति का सामना न किया हो। कोरोना की इस दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिली तो फंगस संक्रमण व डेंगू के डंक ने लोगों को परेशान किया। इस बीच 18 वर्ष से अधिक आयु के 70 प्रतिशत आबादी को टीके की संजीवनी मिलने के बाद लोग कोरोना के ख़ौफ से निकल ही रहे थे कि इस साल का अंत ओमिक्रॉन की दहशत के साथ हो रहा है।

स्थिति यह है कि पिछले वर्ष के मुक़ाबले इस वर्ष कोरोना से दिल्ली में 37.29 प्रतिशत मौतें अधिक हुईं। मार्च में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे और 20 अप्रैल को संक्रमण दर चरम पर थी। मई के मध्य तक इसका असर बरकरार रहा। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण अफरातफरी का माहौल रहा। बत्रा व जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज़ों की मौत होने की बातें भी सामने आई। इस पर सियासत भी बहुत हुई। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का एक कारण यह भी सामने आया कि अस्पतालों में इसके पर्याप्त भंडारण की सुविधा नहीं थी। ऑक्सीजन के लिए दिल्ली दूसरे राज्यों पर निर्भर रही। इसके अलावा कोई खास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। दूसरी लहर का क़हर झेलने के बाद दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारगर क़दम उठाए गए। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि अब यहां 790 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता है। इसके अलावा 442 मीट्रिक टन का बफर रिजर्व भी स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में कुल करीब 121 मीट्रिक टन क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। 30 हजार ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर ली गई है, जिसमें 10,000 आइसीयू बेड शामिल हैं।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले जो रहे सुर्ख़ियों में

18 जनवरी : एम्स के ट्रामा सेंटर में 100 बेड के बर्न व प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक का शुभारंभ हुआ। यह सफदरजंग अस्पताल के बर्न सेंटर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बर्न सेंटर है। इसमें 30 आसीयू बैड व 10 प्राइवेट वार्ड के बैड होंगे। कोरोना के कारण इसमें अब तक बर्न के इलाज की सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई।

19 जुलाई : एम्स में नवनिर्मित मातृ व शिशु ब्लॉक का आंशिक रूप से शुभारंभ। इसमें 427 बेड की सुविधा व 12 ऑपरेशन थियेटर हैं। इस माह एम्स में सर्जरी ब्लॉक में आंशिक रूप से ओपीडी का शुभारंभ।

25 सितंबर : एम्स के मुख्य

बाक़ी पेज 11 पर

लाल क़िले पर कब्ज़े की मांग, उच्च न्यायालय ने कहा - बहुत देरी हुई

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार से लाल क़िले का कब्ज़ा वापस दिलाए जाने की मांग वाली एक महिला की याचिका को ख़ारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का नाम सुल्ताना बेगम है और वह मुग़ल शासक बहादुर शाह ज़फ़र-2 के परपोते की विधवा होने का दावा कर रही है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन मुग़ल शासक को लाल क़िले से निकाल कर कर उसे अपने कब्ज़े में ले लिया था और अब भारत सरकार उनके पूर्वजों की संपत्ति पर कब्ज़ा करके बैठी है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने सुल्ताना बेगम की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि इसे बहुत देरी से दाख़िल किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि दुर्भाग्य से आपने केस बनाए बिना ही याचिका दायर कर दी। आपके मुताबिक, यह सब 1857 और 1947 के बीच हुआ। आपने याचिका में यह तक नहीं बताया कि आपकी परेशानी क्या हैं कोर्ट ने कहा, माना कि याचिकाकर्ता एक अशिक्षित महिला है, लेकिन उसके पूर्वजों ने उसी वक्त या उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

एडवोकेट विवेक मोर के ज़रिए दाख़िल याचिका में बेगम ने कहा कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली के बहादुर शाह ज़फ़र से उनका सिंहासन छीनकर, उनकी सारी संपत्ति को अपने कब्ज़े में ले लिया था। दावा किया कि अंग्रेज़ों ने ज़फ़र को राजद्रोह का दोषी क़रार देते हुए उन्हें यहां से निर्वासित कर परिवार सहित रंगून भिजवा दिया। वहां उनकी पत्नी ने एक बेटे को जनम दिया। 1862 में ज़फ़र की मौत हो गई। उस वक्त वह 82 वर्ष के थे। याचिका में कहा गया कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और यहां की सत्ता भारत सरकार के पास आ गई तो उसने ज़फ़र के परपोते बेदार बख़्त को उनका उत्तराधिकारी मानते हुए 1960 में पेंशन देना शुरू कर दिया। बख़्त को अपने पति बताते हुए बेगम ने याचिका में कहा कि पति के देहांत के बाद उन्हें पेंशन दी जाने लगी, जो इतनी कम है कि उससे जीवनयापन करना तक मुश्किल है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अब भारत सरकार ने ग़ैर कानूनी रूप से उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्ज़ा कर रखा है। इन तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि उसे लाल क़िले का कब्ज़ा वापस देने का भारत सरकार को निर्देश दिया जाए या उसके बदले में मुआवज़ा दिलाया जाए। दूसरी मांग यह रखी कि 1857 से लेकर अब तक क़िले पर अवैध कब्ज़ा करके रखने के लिए उचित मुआवज़ा भी उसे दिया जाए। ❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

क्या टी.एम.सी राष्ट्रीय विकल्प बन सकेगी?

भारत की राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई यह है कि आज देश में केवल दो ही राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें अखिल भारतीय कहा जा सकता है वे हैं भाजपा व कांग्रेस। मगर इन दोनों की स्थिति में यह फर्क है कि भाजपा के लोकसभा में 301 सदस्य हैं और कांग्रेस के 53, विगत लोकसभा चुनावों में कुल पड़े 78 करोड़ से अधिक मतों में कांग्रेस को 12 करोड़ के लगभग मत मिले थे जबकि भाजपा को इसके दोगुने के करीब मत प्राप्त हुए थे। यदि हम पिछले चुनावों में भाजपा व उसके सहयोगी दलों को पड़े मत के प्रतिशत को देखें तो यह 45.5 के करीब था और अकेले भाजपा व कांग्रेस के मत प्रतिशत की बात करें तो यह क्रमश: 34.5 व 19 प्रतिशत के करीब था। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रीय दल थे जिनमें वामपंथी भी शामिल थे मगर इनमें से किसी का भी मत प्रतिशत पांच से ऊपर नहीं था। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि देशभर में जहां लोगों की पहली पसंद भाजपा थी तो दूसरी पसंद कांग्रेस पार्टी थी। मगर पेंच यह है कि विभिन्न क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में काफी मज़बूत थे जिसकी वजह से वे अपने राज्यों की लोकसभा सीटों पर भाजपा के मुक़ाबले विजय प्राप्त करने में सफल हुए परंतु इनमें से कई राज्य ऐसे भी थे जहां कांग्रेस पार्टी का भी इनसे मुक़ाबला हो रहा था।

इस त्रिकोणीय मुक़ाबले में सभी क्षेत्रीय दलों को 216 सीटें प्राप्त हुई मगर कांग्रेस को केवल 53 ही मिलीं। (एक सीट बाद में उपचुनाव में मिली थी) इससे यह आसानी से सिद्ध होता है कि विरोधी पार्टी कांग्रेस का अस्तित्व पूरे भारत में है, हालांकि इसके मत प्रतिशत में गिरावट आई है और इस तरह आयी है कि वह अधिसंख्य उत्तर पश्चिम के प्रदेशों में भाजपा उम्मीदवारों से अधिक मत नहीं ले पायी। जहां तक दक्षिण भारत का प्रश्न है तो कांग्रेस ने इस इलाके की लगभग डेढ़ सौ सीटों में चालीस से ऊपर सीटें जीतीं और कुछ पूर्वोत्तर इलाक़ों से भी विजय प्राप्त की।

दूसरी ओर भाजपा ने उत्तर-पश्चिम के राज्यों में अपना झंडा फहराया और एक तरह से मैदान साफ कर दिया और दक्षिण के कर्नाटक में भी मुक़ाबले की सफलता प्राप्त की। अत: राष्ट्रीय स्तर पर यदि किन्हीं दो दलों की तुलना की जा सकती है तो वे भाजपा व कांग्रेस ही बचते हैं। मगर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़ कर अन्य विरोधी दलों का राष्ट्रीय विकल्प देने की बात कही और इसका नेतृत्व किसी क्षेत्रीय नेता के हाथ में देने का प्रस्ताव रखा और तर्क रखा कि कांग्रेस नेतृत्व में गठित यूपीए अब मौजूद नहीं है अत: क्षेत्रीय दलों को अपना ही गठबंधन बना कर 2024 में भाजपा का मुक़ाबला करना चाहिए। ममता दी भूल रही हैं कि 2024 में चुनाव देश की लोकसभा के लिए होंगे न कि विधानसभाओं के लिए। बेशक इसमें कोई राय नहीं कि उन्होंने अपने राज्य पश्चिमी बंगाल में राज्य स्तर की राजनीति में कांग्रेस को पूरी तरह ख़त्म करके स्वयं ही असली कांग्रेस की शक्ल ले ली है मगर उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी उनके राज्य से कांग्रेस के दो सांसद हैं। इसके साथ यह भी तथ्य है कि पूरे देश में अभी भी 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सीधा मुक़ाबला कांग्रेस पार्टी व भाजपा के बीच होता है। मगर इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास देश चलाने के लिए एक ठोस वैकल्पिक विचारधारा और दृष्टि है जो कि किसी भी क्षेत्रीय दल के पास नहीं है।

इस सच्चाई को भी अगर हम दरकिनार कर दें कि जनता के उस 19 प्रतिशत समर्थन का क्या करेंगे जो उसे 2019 के चुनावों में मिला था? यह इस हक़ीक़त को दर्शाता है कि राष्ट्रीय चुनावों में मतदाताओं का नज़रिया विधानसभा चुनावों से अलग होता है। मत प्रतिशत इस बात का साक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी के क्षरण काल में भी उसका जनाधार राष्ट्रव्यापी है जिसकी क्षमता किसी भी अन्य क्षेत्रीय दल में नहीं अत: यह विचार स्वयं ही हवाई या ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है कि कांग्रेस के बग़ैर भी किसी अन्य विपक्षी राष्ट्रीय विकल्प की कल्पना की जा सकती है। कांग्रेस समूचे विपक्ष को यह छाता प्रदान करती है जिसके नीचे आकर सभी विरोधी दल भाजपा की बारिश से बच सकते हैं। अत: विपक्षी पार्टी शिवसेना का यह कहना उचित है कि केवल यूपीए को मज़बूत बनाकर ही भाजपा का विकल्प पेश किया जा सकता है। ममता बनर्जी जिस ग़ैर भाजपावाद का विमर्श फिलहाल आम जनता के सामने रख रही हैं उसका तब तक राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व हो सकता है जब तक कि इसका नेतृत्व किसी ऐसे पार्टी के हाथ में न हो जिस पर अखिल भारतीय स्तर पर देश के लोग भरोसा न कर सकें। कालांतर में हम देख चुके हैं कि साठ के दशक में चलाये गये डॉ॰ राम मनोहर लोहिया के 'गैर कांग्रेसवाद' का क्या हश्र हुआ था? बेशक उस समय कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी भी अन्य पार्टी के पास शासन करने का अनुभव नहीं था मगर आज तो हालात बदल चुके हैं। लगभग हर क्षेत्रीय पार्टी किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा होते हुए केन्द्र में सत्ता का सुख भोग चुकी हैं और इसके बावजूद इनमें से किसी के पास भी एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पर हो। विकल्प कभी भी तिनके जोड़ कर छत बनाने से नहीं बलिक छत के नीचे तिनके इकट्ठा करके बनता है। ❑❑

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी   क़िस्त-103

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस्लामी मुसावात का ऐलान फ़रमाया, मज़हबे इस्लाम में यह ऊँच नीच नहीं है कि फ़लाँ ख़ानदान ही का इमाम बन सकता है, दीन की वजह से इज़्ज़त फ़लाँ को मिलेगी, मज़हबे इस्लाम में ऐसी कोई ज़मानत और ठेकेदारी नहीं है, जो आदमी भी अ़मले सालेह, तक़वा, डर और परहेज़गारी अपनायेगा, अल्लाह के यहाँ वही मुअ़ज़्ज़ होगा, और वह हर तरह की क़यादत करने का अहल होगा और तुम में सब से ज़्यादा मुअ़ज़्ज़ वे लोग हैं, जो अल्लाह तबारक व तआ़ला के नज़दीक सब से ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं। (अल हुजुरात : 13)

शरीअ़त में कुफ़्व की हैसियत

हमारे इलाक़ों में रिश्तेदारियों के अंदर बराबरी देखी जाती है, यह बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिये कि कुफ़्व और बराबरी यह सिर्फ़ एक इन्तिज़ामी मामला है, आ़म तौर पर एक घराने का जो माहौल होता है दूसरे घराने की बच्ची वहाँ निभाव नहीं कर पाती, इस लिए बतौर इन्तिज़ाम के शरीअ़त ने यह कहा कि चूँकि निकाह तो ज़िंदगी तक का रिश्ता और अक़्द है इस लिए अगर इसका लिहाज़ रख लो, तो अच्छी बात है मगर यह कोई ज़रूरी और फ़र्ज़ नहीं है। (ज़ादुल मआ़द मुकम्मल 1117) लेकिन अगर इस से ऊपर उठ कर जोड़ उसके अलावा भी मिल जाये तो शरअ़न ऐसा निकाह करने में कहीं से कहीं तक भी कोई रूकावट नहीं और नाजायज़ नहीं है, असल मक़सूद यह है कि रिश्तेदारी पक्की होनी चाहिये, निकाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज करो कल तोड़ो, इसी लिए शरीअ़त ने तलाक़ को जायज़ तो रखा है लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि : "अल्लाह की नज़र में हलाल चीज़ों में सब से ज़्यादा ना पसंद तलाक़ है"।

हौज़े कौसर का ज़िक्र

इसी तरह आप ने एक असर अंगेज़ ख़ुतबा दिया, फ़रमाया कि कान खोल कर सुन लो:

मैं आख़िरत में तुम्हारा हौज़े कौसर पर मुंतज़िर रहुंगा, और तुम्हारे ज़रिया से दीगर उम्मतों पर फ़ख़्र करूंगा।

एक रिवायत में आता है कि हर नबी का एक हौज़ होगा, और मेरा हौज़ सब से बड़ा होगा, जिस की लम्बाई चौड़ाई सैकड़ों मीलों तक होगी, और फ़रमाया कि इस में पीने के लिए कटोरे इतनी बड़ी तादाद में होंगे, जैसे आसमानों पर झलकते सितारे कि उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, और मैं वहाँ पर अपनी उम्मत को पानी पिलाऊँगा, सहाबा रज़ि0 ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि या रसूलल्लाह! क़यामत में तो बहुत सारी उम्मतें जमा होंगी, वहाँ यह कैसे पता चलेगा कि यह उम्मते मुहम्मदिया का आदमी है? हमारे हौज़ पर दूसरे लोग यह सोच कर न आ जायें कि यह अच्छा और ख़ूबसूरत है, इस लिए यहाँ लाइन में लग जाओ, पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह बताओ! अगर किसी के घोड़े ऐसे हों कि उनके हाथ पैर बिल्कुल सफ़ेद हों और वह काले घोड़ों में मिल जायें, तो दूर से पहचाने जायेंगे या नहीं? सहाबा ने कहा कि जी हाँ! पहचाने जायेंगे, फिर आप अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में से जो लोग वुज़ू करेंगे और जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुंचेगा, वह ऐसे चमकेंगे जैसे कोई लाइट चमकती है, और उसे देख कर मैं पहचान लुंगा कि यह मेरी उम्मत का आदमी है। (मुस्लिम शरीफ़ 1/126)

ख़बरदार! मुझे रूसवा मत करना

इसके बाद आप ने फ़रमाया कि अच्छी तरह सुन लो! मैं हौज़ पर तुम्हारा मुन्तज़िर रहूंगा, और तुम्हारे ज़रिया से लोगों पर फ़ख़्र करूंगा, लेकिन तुम अपने नामा-ए-आमाल सियाह कर के मुझे वहाँ रूसवा मत करना।

"मेरा चेहरा सियाह मत करना।"

यह ऐसा जुमला है कि आदमी को पकड़ कर झंझोड़ दे। पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम सहाबा के वास्ते से हम से फ़रमा रहे हैं कि हुज़ूर तो फ़ख़्र करेंगे कि यह नमाज़ी और परहेज़गार है लेकिन उस में अगर कोई बद अ़मल निकल आया, तो कहा जायेगा कि यह आप का उम्मती है? तो आप पर कितना असर होगा?

ज़रा ग़ौर करें

आज हम अपना हाथ दिल पर रख कर सोचें, हम कितने काम सुबह से शाम तक ऐसे करते हैं जिस से हमारे आक़ा व मौला को अज़ीयत(तकलीफ़) होती है?ख नाम लेने वाले और मुहब्बत का ज़बानी इज़हार करने वाले तो बहुत हैं। चंद रूसूमात को मुहब्बत समझ कर नाम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन जिन सुन्नतों के सही और सच होने का पूरी तरह यक़ीन है उनके बारे में हर आदमी अपने गिरेबान में झाँक कर देखे कि हम उन तरीक़ों पर चलने वाले हैं कि नहीं? एक बाप अपने बेटे की ग़लती पर जिस तरह कुढ़ता है, जितनी कुढ़न उस बाप को अपने बेटे पर होती है उस से लाख दर्जे कुढन पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम को अपने उम्मती के ग़लत तरीक़े पर होती है। इस लिए कि पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम को अपने उम्मती से उस से हज़ार और लाख दर्जे ज़्यादा तअ़ल्लुक़ है, जितना एक बाप को अपने बेटे से हो सकता है। (जारी)

हमारा सारा काम व राजनीति बाबा साहेब से प्रेरित है

मनीष सिसौदिया

बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ग़रीब घर में पैदा हुए और संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। वह चाहते थे कि देश का हर बच्चा चाहे वह कितना भी ग़रीब क्यों न हो, उसे अच्छी शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए ज़ोर शोर से लगी हुई है। डॉ. आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। दिल्ली सरकार बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए किस तरह से काम कर रही हैं और क्या ख़ास योजनाएं हैं यह सब जानने के लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया से विशेष बातचीत हुई, पेश इस बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्न:- दिल्ली सरकार ने बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण रहा..?

उत्तर:- हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जिसे दिलाने से लेकर आज़ाद भारत में कैसे जीएंगे। एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, क़ानूनी सुविधाएं कैसे लेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं सबको कैसे मिलेंगी, इन सब चीज़ों के लिए आधुनिक भारत के आर्कीटेक्ट हमारे बाबा साहेब ही हैं। उन्होंने कितने अभाव में कितनी प्रताड़ना के बीच सब नियम क़ानून बनाएं, संविधान लिखा। यह बातें लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उनके विज़न पर चलते हुए आज़ाद भारत के 75 वर्ष हुए हैं। वह कहां पैदा हुए, क्या क्या संघर्ष किए, क्या सोचा? यह सब दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नाटक का आयोजन दिल्ली सरकार करने जा रही है। यह नाटक 05 जनवरी से शुरू किया जाएगा।

प्रश्न:- संभवत पहली बार कोई सरकार किसी संदेश को देने के लिए इतने बड़े स्तर पर नाटक का आयोजन कर रही है। इसको करने का विचार कैसे आया..?

उत्तर:- विकसित देशों को देखें तो वहां इस तरह के बहुत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहां प्रतिष्ठित लोगों पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस माध्यम को अपनाते हैं। वहां की सरकारों के कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से थिएटर के आयोजन किए जाते हैं। मैंने थिएटर की कई रिर्कार्डिंग देखीं, फिर सोचा कि हमारे नेताओं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, आजाद भारत को गढ़ने वालों आदि विभूतियों के लिए भी तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए।

प्रश्न:- बाबा साहेब के जीवन पर आधारित नाटक के विषय में भी विस्तार से बताइए.?

उत्तर:- बाबा साहेब ने जितना बड़ा काम किया, उतना बड़ा तो थिएटर नहीं हो सकता लेकिन बड़ा थिएटर करके उसे दिखाकर देखने वालों को प्रेरित ज़रूर किया जा सकता है। नाटक में बड़े बड़े आर्टिस्ट और डायरेक्टर हों। उसका आर्कीटैक्ट बड़ा हो। आधुनिक भारत बनाने में बाबा साहेब ने योगदान कैसे दिया, इसे तीन घंटे बैठकर लोग समझें और फिर सोचें कि वे समाज में क्या योगदान कर सकते हैं।

प्रश्न:- बाबा साहेब का जीवन संघर्षों व असीम सफलता की अनूठी कहानी है तो उनके जीवन के आदर्शों मूल्यों को आप कैसे जोड़ रहे हैं..?

उत्तर:- देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, बाबा साहेब का यह सपना था। बाबा साहेब की बातें तो बहुत की गईं लेकिन सपने को पूरा किसी ने नही किया। अब दिल्ली सरकार अच्छी शिक्षा देकर उसे पूरा कर रही है। उसके साथ हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति को भी सम्मानजनक ढंग से मिलें। उनको भीख न मांगनी पड़े। इसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। एक बच्चे को घर में पढ़ना है तो बल्ब जलाने के लिए बिजली चाहिए हम गरीब को मुफ़्त बिजली दे रहे हैं।

प्रश्न:- बाबा साहेब राजनीति के केन्द्र में रहते है। कई पार्टियां हैं जिनके चिह्न के रूप में वह नज़र आते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए बाबा साहेब और उनके विचार क्या मायने रखते हैं..?

उत्तर:- हमारा सारा काम, राजनीति उनसे प्रेरित है। बाकी पार्टियों के साथ दिक्क़त यह हो गई कि उन्होंने बाबा साहेब को प्रतीक चिह्न तक या टेक्सट बुक तक सीमित कर दिया। हम नाटक आयोजित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि लोग एक बार थिएटर में जाकर देखें और बाबा साहेब के जीवन को पूरा अनुभव करते हुए उसे जीएं। हर बच्चा और आम आदमी प्रेरणा लें। इसलिए नाटक को इतने बड़े स्तर पर आयोजित कर रहे हैं।

प्रश्न:- बाबा साहेब वंचित और ग़रीब वर्ग के लिए काम करने में सदा ही लगे रहते थे, दिल्ली सरकार इस वर्ग को लाभ देने के लिए कैसे काम कर रही है..?

उत्तर:- शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, उच्च शिक्षा की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मजदूरों की बात हो रही है तो झुग्गी और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की बात हो रही है। उनके लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार दो स्तर पर काम कर रही हैं आर्थिक रीढ़ को मज़बूत करने के लिए व्यापारी वर्ग पर ध्यान दे रही है। उसके अनुसार योजनाएं बनाई गईं ताकि व्यापार बढ़े। टैक्स कम किए, डोर स्टैप डिलीवरी की सुविधा, इंस्पेक्टर राज ख़त्म किया। व्यापारी यही चाहता है कि सरकारी खानापूर्ति को कम कर ज़िन्दगी आसान बना दी जाए। हमने वही किया। चौबीसों घंटें बिजली दी ताकि व्यापार न रुके। यह वर्ग संतुष्ट हुआ तो कारोबार बढ़ा और दिल्ली सरकार के पास टैक्स आया। टैक्स के पैसे का उपयोग दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए किया।

प्रश्न:- आपने वित्त क्षेत्र में भी अच्छा काम किया हैं दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि भविष्य में दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय सिंगापुर की प्रतिव्यक्ति आय के बराबर होगी इसका रोडमैप क्या है..?

उत्तर:- हम कह रहे हैं कि 2047 में दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर होगी। हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं जो अब पैदा हो रहा है और तब उसकी आयु 25 वर्ष के करीब होगी। उसे सक्षम बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत कर रहे हैं। बिजनैस ब्लास्टर्स जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली का युवा नौकरी देने वाला बने। अब जो बच्चा है वह आगे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगा। उसे अच्छी शिक्षा दी जा रही है, ताकि आगे चलकर वह सिंगापुर के युवा से अधिक कमाए।

प्रश्न:- पंजाब में चुनावी सरगर्मिया तेज़ हैं। आप ने भी कई बार दौरा कर लिया। वहां की स्थितियों को लेकर आपका आंकलन क्या है?

उत्तर:- मेरा आंकलन है कि पंजाब के लोग सोच रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को एक मौक़ा देना चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया है। अब मौक़ा आ गया है कि पंजाब में भी काम करने का अवसर दिया जाए। इस तरह का मन बन रहा है लोगों का। मैं पंजाब में चारों ओर गया लोग यही कह रहे हैं केजरीवाल को

बाकी पेज 11 पर

देवेगौड़ा मानसिक सदमे से गुज़रे थे जब उनके बेटे भाजपा में चले गए, यह उनकी इच्छा के विरुद्ध था : सुगाता

प्रश्न:- आपने अपनी किताब में देवेगोड़ा के लिए लिखा है कि 'वह अपनी सारी अपूर्णताओं के योग से अधिक हैं।' इसे समझाएं क्योंकि यहीं पंक्ति नेहरू जी के लिए भी एक लेख में लिखी गई थी..?

उत्तर:- नेहरू जी पर जो लेख, उसकी पंक्ति है, 'नेहरू अपनी सारी अपूर्णताओं के योग से कई कई गुना ज्यादा हैं।' इसे आप देवेगोड़ा पर भी लागू कर सकते हैं चूंकि वह दक्षिण से हैं और हिंदी भाषी नहीं हैं, इसलिए उन्हें लेकर भ्रांतियां हैं। वह हमेशा इस बात को लेकर सचेत रहते थे कि वह नेहरू की कुर्सी पर बैठ रहे हैं लेकिन विडंबना देखिए कि उन्हीं की कांग्रेस ने देवेगौड़ा को सत्ता से बाहर कर दिया। फिर भी, उन्होंने हमेशा कहा कि नेहरू ने हमें एक महान देश दिया और संवैधानिक लोकतंत्र दिया। यह देवेगौड़ा की भी सोच थी कि भारत संभाला नहीं जा सकता था अगर नेहरू न होते, उनका दृष्टिकोण न होता।

प्रश्न:- आपकी किताब दावा करती है कि देवेगौड़ा का धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर पूरा भरोसा है। उनके निजी और सार्वजनिक जीवन में आपको उनकी यह समझ कितनी दिखी..?

उत्तर:- देवेगौड़ा कोई समाजशास्त्री या अकादमिक नहीं हैं। मैंने उन्हें करीब से देखा है - प्रार्थना करते हुए, लोगों से बात करते हुए मुझे नहीं लगता कि वह किसी धर्म में भेद करते होंगे। वह अपपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह नहीं कहते कि मेरा भगवान किसी से महान या बड़ा है। उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने में भी झिजक नहीं दिखाई। जब वह प्रधानमंत्री पद छोड़ रहे थे, तब तक वाजपेयी का साथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वर्ष 1996 में वह अपने पिता के बारे में संसद में बोले कि उन्होंने सिखाया है कि भगवान हर जगह है, इस संसद की दीवारों में भी। असल में देखिए कि देवेगौड़ा कैसे दुख और मानसिक सदमे से गुज़रे जब उनके बेटे भाजपा में चले गए। यह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ।

प्रश्न :–छह दशक के राजनीतिक कैरियर के बाद भी देवेगौड़ा के पास सत्ता 8 वर्ष से कम रही। कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी के नज़दीक आने के बाद जब 1994 में उनके पास सत्ता आई, तो वह 96 में दिल्ली चले गए। उन्होंने कभी अपना कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया। आप इस तथ्य का विश्लेषण कैसे करते हैं..?

उत्तर:- वह पहले 23 वर्ष तो विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की। सन 1983 में वह मुख्यमंत्री बनने को थे, लेकिन चन्द्रशेखर ने उनसे विनती की कि वह हट जाएं और रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री बनने दें। उनके पास चार और अवसर आए, लेकिन वह पांचवीं बार में मुख्यमंत्री बने। इधर, दिल्ली में हालात विपरीत थे। ज्योति बसु की पार्टी और वीपी सिंह नहीं माने। वह ज्योति बसु को बड़ा भाई मानते थे। उन्होंने उनके पांव पकड़ते हुए कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, कर्नाटक की सत्ता में रहना है लेकिन बसु और सुरजीत ने उन्हें चुना, तो एक वजह यह भी थी कि वह शूद्र थे। मैंने येचुरी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वह एक दलित राष्ट्रपति और शूद्र प्रधानमंत्री चाहते थे।

प्रश्न :–हेगड़े और देवेगौड़ा की राजनीति प्रतिस्पर्धा में जाति का प्रश्न कर्नाटक की राजनीति को कैसे मथ रहा था?

उत्तर:- देवेगौड़ा एक प्रभुत्ववादी वोक्कालिंगा समुदाय से हैं। लिंगायत उनके विपक्ष का दूसरा बड़ा समुदाय था। अगर अंकों की बात करें तो रामकृष्ण हेगड़े और देवेगौड़ा की तुलना ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण वहां अल्पसंख्यक थे। 1970 के बाद देवेगौड़ा ही हेगड़े की जीत सुनिश्चित कराते रहे। देवेगौड़ा लोगों से घुलते मलते, साथ ही उनके पास संख्या बल था। हेगड़े एक बेहतर मुख्यमंत्री थे, लेकिन वह नहीं कर पाते। देवेगौड़ा ही हमेशा किंगमेकर थे। ❑❑

भारतीय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कैसे बने?

यह तथ्य है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या यह सत्य है कि वह सबसे अच्छा लोकतंत्र भी है? वह सबसे बड़ा तो सिर्फ इसलिए है कि उसकी जनसंख्या किसी भी बड़े से बड़े लोकतंत्र से पांच गुनी या दस गुनी है। संख्या बल हमारे लोकतंत्र को अनुपम बनाता ही है, उसकी विविधता भी उसे विलक्षण रूप प्रदान करती है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपने- अपने लोकतंत्र को अतिविशिष्ट बता सकते हैं, लेकिन क्या उनके यहां भारत के समान दर्जनों, धर्म, संप्रदाय, भाषाएं, रीति रिवाज़ और हज़ारों जातियां हैं? क्या उन्हें कभी इतनी विविधताओं का सामना करना पड़ा है? क्या वे लोकतांत्रिक देश भारत की तरह सैकड़ों वर्ष विदेशियों की गुलामी में कभी पिसते रहे हैं?

भारत की तरह सात-आठ दशक पहले आज़ाद हुए एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों से तुलना करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत एक बेजोड़ राष्ट्र है। ज़रा हम अपने पड़ोसी देशों पर पहले नज़र डालें। लगभग सभी देशों के संविधान बदल चुके हैं। पाकिस्तान, अफग़ानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों के कई कई नए संविधान आ चुके हैं, लेकिन भारत का मूल संविधान आज भी ज्यों का त्यों हैं। वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उसे वैसा होना ही था, क्योंकि वह इतने विविधतामय राष्ट्र को संहालने के लिए बनाया गया था। वह ज्यों का त्यों है लेकिन वह इतना लचीला भी है कि उसमें लगभग सवा सौ संशोधन हो चुके हैं।

इतने बड़े राष्ट्र को यह संविधान संभाले हुए हैं, इसीलिए भारत में आज तक कोई फौजी या राजनीतिक तख़्ता पलट नहीं हुआ। किसी भी दक्षिण एशिया के राष्ट्र का नाम बताए, जहां इतने शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन होता रहा हो। इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपने का दुस्साहस किया 1975 में ज़रूर किया लेकिन अगले दो साल पूरे होने के पहले ही भारत की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदख़ल कर दिया। एक दो राष्ट्रपतियों और सेनापतियों के बारे में ये अफवाहें ज़रूर सुनने में आई थीं कि वे कुछ दुस्साहस करना चाहते थे, लेकिन भारतीय लोकभय ने लोकतंत्र की रक्षा की और वे अपनी मर्यादा में रहने को मजबूर हुए।

भारतीय लोकतंत्र सामाजिक और धार्मिक विविधता को साधे रखने में तो सफल हुआ ही है, वह राजनीतिक विविधता का संतुलन बनाए रखने में भी कुशल सिद्ध हो रहा है। वह ज़माना गया, जब केरल की कम्युनिस्ट सरकार को नेहरू काल में और इंदिरा व मोराजी देसाई काल में विरोधियों की प्रांतीय सरकारों को अकारण ही बर्खास्त कर दिया जाता था। अब केन्द्र में चाहे किसी भी दल की सरकार हो..। चाहे कांग्रेस की रही हो..या आज भाजपा की हो। ये सरकारें काफी मजबूत होते हुए भी राज्यों की विपक्षी सरकारों को बर्दाश्त करती रहती हैं। यही राजनीतिक विविधता का संतुलन है।

इन सब ख़ूबियों के बावजूद क्या हम अपने लोकतंत्र की वर्तमान दशा से संतुष्ट हो सकते हैं? क्या हम उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कह सकते हैं? फिलहाल तो नहीं कह सकते लेकिन हमारी जनता और नेता कोशिश करें तो सचमुच भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बन सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे लोकतंत्र की कमियों को खोजें और उनका निवारण करें। व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार को ख़त्म करना देश की सबसे पहली ज़रूरत है क्योंकि यह व्यवस्था ही है...जो अनेक सुधारवादी क़दमों को पूरा होने से पहले ही रोक लेती है।

वोट..नेताओं की प्रसिद्धि का एक पैमाना हो सकते हैं। हमारे दर्जनभर से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री हो गए हैं लेकिन कितने प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में 51 प्रतिशत से ज़्यादा वोट मिले हैं? पीवी नरसिम्हा राव और नरेन्द्र मोदी के अलावा किसी भी प्रधानमंत्री को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नेहरू और इंदिरा को भी नहीं। यही हाल हमारी संसद का भी है। संसद के लगभग साढ़े पांच सौ सदस्यों में से 50 भी प्राय: ऐसे नहीं होते, जिन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में 51 प्रतिशत से अधिक मत मिले हो। दूसरे शब्दों में इसे यूं कहा जा सकता है कि हमारे नेता और सांसद ठोस बहुमत से ही चुने जाने चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान दिवस पर कहा कि भारतीय लोकतंत्र को परिवारवाद ने लंगड़ा कर दिया है। हमारे देश में भाजपा और माकपा के अलावा सभी पार्टियां अब पार्टियां कहां रह गई हैं? वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। कोई मां बेटा पार्टी, कोई बाप-बेटा पार्टी है, कोई भाई-भतीजा पार्टी है तो कोई भाई भाई पार्टी है। जो पार्टियां ऐसी नहीं हैं, क्या उनमें भी आंतरिक लोकतंत्र है? क्या उनके मंत्रिमंडलों, पार्टी मंचों और विधानसभाओं व लोक सभाओं में उनके सदस्य खुलकर अपनी बात रख पाते हैं? उनके पदाधिकारियों की नियुक्तियां मुक्त चुनाव से होती हैं? बात कहने की आज़ादी का पालन सबसे पहले दलों के आंतरिक लोकतंत्र में होना चाहिए। अपने लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए इस कमी को दूर करना ज़रूरी है।

भारतीय लोकतंत्र को भेड़तंत्र बनाने का सबसे ज़्यादा दोष जातिवाद को है। सभी पार्टियां थोक वोट हासिल करने के लिए जातिवाद का ही सहारा लेती हैं। चुनावों से जातिवाद को ख़त्म करने का एक तरीक़ा यह भी है कि किसी ख़ास चुनाव क्षेत्र से किसी खास उम्मीदवार को खड़ा करने

बाक़ी पेज 11 पर

प्लांटेशन में है असीम संभावनाएं

इस क्षेत्र में काम करने वालों को प्लांटवर्क, प्रोसेसिंग, ऑक्शनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और रिसर्च है। प्लांटेशन वर्क में चाय के पौधों को बड़ा करना होता है, जिसमें मिट्टी को तैयार करना, सही खाद का इस्तेमाल करना, सही वातावरण तैयार करना, पत्तियों को तरीके से तोड़ना आदि शामिल है। प्रोसेसिंग वर्क में पत्तियों का चूरा बनाना, तोड़ना और घुमाना शामिल है, जो फैक्ट्री में होता है। इसके बाद, चाय को पैक करके नीलामी केन्द्रों में भेजा जाता है। यहां विभिन्न प्लांटेशन से आए चाय के सैम्पल्स को टेस्ट, ब्लेड और ब्रांड में पैक किया जाता है। प्लांटिंग, टेस्टिंग और मार्केट ट्रेंड की जानकारी रखने वाले टी ब्रोकर्स चाय की नीलामी करते हैं और मार्केटिंग से संबंधित व्यक्ति फाइनल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। हालांकि अब विभिन्न तरह की चाय को ब्लेंड करने के लिए कम्प्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा है, फिर भी टी टेस्टर के निर्णय को अंतिम माना जाता है।

शिक्षा

आधारभूत शिक्षा प्राप्त व्यक्ति चाय इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकता है और धीरे-धीरे काम की बारीकियां सीख सकता है। हालांकि एग्रीकल्चरल साइंस या बॉटनी/फूड साइंस/हार्टिकल्चर में बी.एस.सी. वालों को प्राथमिकता दी जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट या मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग की नौकरी के लिए रखा जाता है। नए लोगों को प्लांटेशन स्तर पर काम करने के लिए बतौर सहायक रखा जाता है। इसके बाद ही उसे असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर बनाया जाता है। टी टेस्टर्स को चुनकर ट्रेनिंग दी जाती है। नेचुरल टैलेंट के अलावा, कुछ साल के लिए कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद टेस्टिंग मैनेजर पद मिलता है। इन्हें मैनेजरियल स्किल्स और मार्केटिंग क्षमताओं पर भी काम करना होता है।

व्यक्तिगत क्षमता

ऐसे लोगों को ही यह क्षेत्र चुनना चाहिए, जो दिलचस्प और आउटडोर ज़िन्दगी को पसंद करते हों। प्लांटेशन/फैक्ट्री मैनेजरों का फिजिकली फिट, एडैप्टेबल और सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है। नेतृत्व के गुण और मज़दूरों के साथ डील करने की क्षमता भी होनी चाहिए। चाय बाजार के बारे में जानकारी और मार्केटिंग का भी पता होना ज़रूरी है। टी एस्टेट के ज्योग्राफिकल लोकेशन और टोपोग्राफी की जानकारी भी हो। ब्रोकर बनने वालों का दिमाग़ सही और अनुशासन में होना चाहिए। निर्माताओं और खरीददारों के साथ दोस्ती निभाना ज़रूरी है।

विकल्प:- चाय कंपनियां, चाय बागान, ब्रोकिंग हाउस, एसोसिएशन और टी बोर्ड ऑफ इंडिया में नौकरी के अवसर हैं। अनुभवी टी प्लांटर टी ब्रोकर या टी टेस्टर बन सकता है। सीनियर प्रोफेशनल्स एडवाइजर/ कंसल्टेंट बन सकते हैं। पढ़ाई में रुचि रखने वाले टी प्लांटेशन्स में रिसर्चर पद पा सकते हैं।।

टी टेस्टर:- इनका काम चाय के विभिन्न फ्लेवर्स के बीच अंतर को बताना है और गुणवत्ता के मुताबिक ब्रांडिंग करना हैं अधिकतर चाय कंपनियां टी टेस्टर को अपने यहां रखती हैं ताकि क्वालिटी स्टैंण्डर्ड बना रहे। टी टेस्टिंग की नौकरी पर रहकर ही सीखा जा सकता है। विभिन्न चायों के स्वाद और अरोमा को समझने का ज्ञान सीखा जाता है। इन्हें मैनेजरियल के साथ मार्केटिंग स्किल्स भी आना चाहिए। टी टेस्टर्स के विकसित टेस्ट बड्स होने चाहिएं और उन्हें अपने सेसिटिव को साफ रखना चाहिए। इन्हें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और स्पाइसी फूड खाते रहना चाहिए। इस नौकरी की कमी यह है कि मौसम के दौरान एक दिन में 200-300 कप का स्वाद लेना होता है, जो दांतों में धब्बे बना देता है और पाचन तंत्र को कमज़ोर बना देता है। इन्हें आयात-निर्यात के काम के साथ रिसर्चर को टेस्ट, इकोनॉमिक वायबिलिटी और मैच्योरेबिलिटी पर सलाह भी देते हैं। घरेलू और विदेशी बाजारों पर भी इन्हें नज़र रखनी पड़ती हैं कई युवा इसे बतौर कैरियर अपनाते हैं, क्योंकि यह काम अलग ढंग से होता है और सैलरी भी ज़्यादा मिलती है।

रिसर्चर:- इस इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है शोध करते रहना। बोटानिस्ट, बायो-टेक्नोलॉजिस्ट और अन्य वैज्ञानिक चाय पर शोध करते रहते हैं। ये टी टेस्टर्स से टेस्ट, इकोनॉमिक वायबिलिटी और मैच्योरेबिलिटी पर सलाह देते हैं। असम के जोरहट स्थित टी रिसर्च एसोसिएशन में चाय पर शोध सबसे अधिक किया जाता है। रिसर्च एसोसिएशन के साथ टी प्लांटेशन भी रिसर्च के लिए लोगों को अपने यहां नौकरी पर रखते हैं।

ब्रोकर:- प्लांटर प्रोडयूसर और खरीददार के बीच ब्रोकर काम करता है। मार्केट ट्रेंड के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नज़र रखता है। टी इंडस्ट्री में बैकग्राउंड और टी टेस्टिंग क्षमता वाला ही ब्रोकर बनता है। नीलामी केन्द्रों पर चाय के सैम्पल को ब्रोकर ही सूचिबद्ध करता है। भारत में कई ब्रोकिंग हाउसेज हैं, जहां ब्रोकर चाय बागानों से आए चायों की सैंपलिंग करता है।

कंसलटेंट:- द टी बोर्ड ऑफ इंडिया और कई टी एसोसिएशन कंसल्टेंट को नौकरी पर रखते हैं। अनुभवी टी प्लांटर्स कंसल्टेंसी सर्विस का काम दे सकते हैं। वे बता सकते हैं कि चाय के पौधों, स्रोत के बारे में बताने के अलावा लोगों को ट्रेनिंग भी देने का काम करते हैं।

व्यक्तिगत आमदनी

कई कमियों के बावजूद युवा इसे बतौर कैरियर इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि यहां सैलरी अच्छी होने के साथ ही बंगला, गाड़ी और आकर्षक इंसेंटिव भी हैं। ट्रेनी को 8,000 प्रतिमाह मिल जाता है। तो सीनियर प्रोफेशनल्स को 30,000 प्रतिमाह। विशेषज्ञों को 50,000 रुपये प्रति माह मिल जाता है।

शिक्षण संस्थान

- असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, बेंगलुरू।
- दीपरस इंस्टीटयूटस ऑफ प्रोफेशनल्स स्टडीज, कोलकाता।
- एनआईटीएम, दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, पश्चिमी बंगाल।
- असम दार्जिलिंग टी रिसर्च सेंटर, दार्जिलिंग।
- यूपीएएसआई टी रिसर्च इंस्टीटयूट, तमिलनाडू।
- बिडला इंस्टीटयूट ऑफ फ्यूचरिस्टिक स्टडीज, कोलकाता।
- द टी टेस्टर्स एकडमी, केरल। ❑❑

इस्लामी दुनिया

सुलेमानी की हत्या के पीछे था इजराइल

येरुशलम : इजराइली सेना के खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख का कहना है कि जनवरी 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराने वाले अमरीकी हवाई हमले में उनका देश भी शामिल था। इस अभियान में इजराइल के शामिल होने की बात पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई है। सुलेमानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के 'कुद्स फोर्स' के प्रमुख थे और विदेशों में अर्धसैनिक बलों के साथ ईरान के संबंधों की ज़िम्मेदारी उठाते थे।

पाक-ईरान, व तुर्की को जोड़ने वाली ट्रेन 10 वर्ष बार फिर शुरू

इस्लामाबाद : पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को जोड़ने वाली एक मालगाड़ी सेवा फिर से शुरू की गई है। यह सेवा, 10 से अधिक सालों तक निलंबित रही। तीनों देशों की योजना भविष्य में इसी मार्ग पर एक यात्री रेल सेवा शुरू करने की भी हैं। पाक रेल मंत्री आज़म खान स्वाति ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद के साथ के साथ यहां मार्गल्ला रेलवे स्टेशन पर इस्लामाबाद-तेहरान, इस्तांबुल मालगाड़ी शुरू की।

भारतीवंशी उज़रा जेया को तिब्बती मुद्दों का संयोजक बनाया

अमरीका ने तिब्बत के मुद्दों के लिए भारतीय मूल की राजनयिक उज़रा जेया को अपना विशेष संयोजक नियुक्त किया है। उन्हें तिब्बत पर एक समझौते के लिए चीन और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच ठोस बातचीत को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। इस नियुक्ति से बौखलाए चीन ने कहा है कि वह ज़ियाद के पद को मान्यता नहीं देगा। यह चीन के आंतरिक मामलों में अमरीका का हस्तक्षेप है।

लिंचिग इस्लामी तालीमाल ख़िलाफ़

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के शीर्ष धार्मिक निकाय ने कहा कि कानून को हाथ में लेना कुरआन, शरीयत की शिक्षाओं संविधान के ख़िलाफ़ है। निकाय ने देश के पंजाब प्रांत में श्रीलंकाई नागरिक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के दोषियों को कानून के हवाले करने की मांग करते हुए यह बात कहीं। पिछले दिनों ईशनिंदा के आरोप पर सियालकोट में प्रियंता कुमार दियावदाना की पीटकर हत्या कर लाश को हाग लगा दी गई थी।

स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए आवश्यक है मतदाताओं का मुखर होना

लक्ष्मीकांत चावला

भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां हो गई हैं। अमृत महोत्सव अर्थात् स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव। इस संदर्भ में कई बार डाक्टर राधाकृष्ण जी के शब्द याद आते हैं - उन्होंने लिखा था कि बहुत समय पहले भारत स्वतंत्र गांवों का स्वतंत्र देश था। इसके पश्चात् स्वतंत्र गांवों का परतंत्र देश बना और खेद है कि आज भारत देश तो स्वतंत्र है पर भारत की मानसिकता अंग्रेज़ और अंग्रेजियत से प्रभावित है। कई बार यहां यह कहा जाता था कि अपनी भाषा है भली, भलो अपनो देश जो कछु है अपनो भलो यही राष्ट्र संदेश। आज की स्थिति यह हो गई कि देश की अधिकतर जनता ने आंखें मूंद कर वह सब अपना लिया जिससे भारतीय जीवन मूल्यों का कोई नाता ही नहीं।

गली, गांव, बाज़ारों में घूमिए, भारतीय भाषाएं ग़ायब हो गईं। हमारे रीति रिवाज़ पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते जा रहे हैं। अमृत महोत्सव में भी जो दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालयों में होंगे या हो रहें हैं वहां देश के कड़ी संख्या में विश्व विद्यालय डायर और मेकाले के काले गाउन पहनकर दीक्षा नहीं, अपितु डिग्रियां बांटेंगे। जब देश के शीर्ष पदों पर बैठे नेता और शासक इस विदेशी गुलामी के प्रतीक लबो ओढ़ लेते हैं तो विद्यार्थी क्या करें। मेरा अपना अनुभव यह है कि अब विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, मतदाताओं को, आम जन को बोलना ही होगा। हमारा लोकतंत्र इसीलिए दल बदलुओं के हाथ में है। इसलिए जन प्रतिनिधि जनता के सेवक नहीं, अपितु शोषक बनते जा रहे हैं क्योंकि कोई रोटी की मजबूरी में, कोई नौकरी की बेबसी, कोई नेताओं के दरवाज़ों पर घुटने टेक कर कुछ पाने के लालच में जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करता जा रहा है।

स्वतंत्रता के बाद विभाजित कटे फटे भारत को संभालने में ही पन्द्रह वर्ष चले गए और 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हो गया। हमने वहां यह अपना संकल्प तो दोहरा लिया कि जो खून बहा सरहद पर वह खून है हिन्दुस्तानी। 1962 के आक्रमण का यह लाभ हो गया कि हम शत्रुओं से लोहा लेने को तैयार हो गए और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई। अफसोस यह कि हम सब भारतवासी और हिंदी है हम वतन है का पवित्र मंत्र धीरे-धीरे चुनावी रणवीरों ने फीकी कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो सादगी का रास्ता दिखाया। अपने आंगन में गुलाब के फूलों की जगह कनक और गोभी के फूलों को स्थान दिया, पर उनके पश्चात् देश में ग़रीबी हटाओं के नारे तो खूब लगे, पर गरीबी न हटी।

आज भी सुरसा के मुंह की तरह खुला है उसके बंद होने की कोई आशा ही नहीं, अपितु दुराशा है कि अब तो वोट लेने के लिए जातिवाद, प्रांतवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है जिस देश की सीमाओं की रक्षा और बलिदान हिन्दुस्तानी खून करता है वहां से अब यह आवाज़ आने लग गई है कि महाराष्ट्र में बाहर के लोगों को काम नहीं मिलेगा। हरियाणा किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को और पंजाब में भी अब यही प्रतिक्रिया हो रही है कि पंजाब के बाहर के लोगों को काम क्यों दिया गया। यह परमात्मा का धन्यवाद है कि वर्तमान सरकार के केवल कुछ दिन शेष हैं अन्यथा यह सरकार भी जाने से पहले पंजाब में सरकारी या ग़ैर सरकारी सेवा में लगे दूसरे प्रांतों के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाती। आज ज़िम्मेवादी जनता की है, जनता नेताओं से चुनाव पूर्व सीधी बात करे। हमें रोटी का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, पर क्या सबको रोटी और शिक्षा मिल रही है? स्वास्थ्य सेवाएं जनता को देना सरकार का काम है। यहां तो गंगा उल्टी बह रही है। जनता बेचारी किसी सरकारी अस्पताल के बाहर अपने परिवार, परिजनों के उपचार के लिए तड़पती है, पर इसी बेचारी जनता के पैसे से लोकतंत्रीय महाराजा बने जनप्रतिनिधि छोटी सी बीमारी के लिए भी जनता के खून पसीने की कमाई लेकर विदेशों में जाकर इलाज करवाते हैं जो राजय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होने का भरोसा दिया गया था वे अब राजनेता सुखाय, अधिकारी सुखाय और सत्तापति हिताय हो गया।

देश में चुनावों का मौसम है। जनता को अपने-अपने क्षेत्र के नेताओं से सामाजिक शिष्टाचार रखते हुए यह पूछा होगा कि देश में बढ़ती महंगाई के साथ ठेका कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं बढ़ा। जो सरकारी सेवा में लगा अस्थायी कर्मचारी दस वर्ष पहले सात आठ हजार रुपये में गुज़ारा करता था, आज बच्चों का पिता बनकर भी बढ़ती महंगाई से उसी 7-8 हज़ार के साथ जूझ रहा है। बड़े-बड़े भाषणों के बाद घोषणा हो गई स्मार्ट सिटी बनेंगी। स्मार्ट का अर्थ सीधा साधा यही है कि ठेकेदारों को करोड़ों रुपयों का काम मिलेगा। बना हुआ शहर तोड़ा जाएगा। शहर के लोगों को धूल और मिट्टी, चौड़ी सड़कें तंग करने का काम और वीआईपी कारें दौड़ाने के लिए एक मुलायम सड़क मिल रही है।

वैसे सवाल यह भी है कि जहां देश के लोग ही स्मार्ट नहीं बन पाए, अस्सी वर्ष का बुज़ुर्ग भी अस्सी किलो भार उठाकर या रिक्शा खींचकर या पेट के बल ठेला चलाकर रोटी कमाने को मजबूर है, बुढ़ापा पेंशन भी न मिल पाए, वे किस स्मार्टनेस की बात करते हैं। हमारे नेताओं की खुशकिस्मती इतनी है कि चुनावी समर में उन्हें कोई सीधा सवाल करने का साहस नहीं करता, लोग डरपोक नहीं, पर सत्ता के नशे में विजयी विधायक या सांसद उनसे किस रूप में बदला लेंगे इससे अवश्य डरते हैं। भारत को नशा मुकत बनाने की बात कही गई। नशा मुक्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि राजनीति स्वार्थ इस देश में काम करता है। शराब मुक्त भारत बनाने के लिए पूरा प्रयास इस देश में हो रहा है। वैसे कितनी हास्यापद बात है कि पंजाब का एक अकाली नेता आप नेता को शराबी कह दे तो झगड़ा हो जाए, पर शराब पीने पिलाने का पूरा काम सरकारें करती हैं, बेचती हैं, बांटती हैं, नोट कमाती हैं। देश के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, नारे लगते हैं पर बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और देश की जवानी को दिशा देने में असमर्थ देश का नेतृत्व के कारण हमारी नई पीढ़ी विदेशों की ओर भाग रही है, पर भाषणवीर नेता उन्हें विदेश जाने से नहीं रोक पा रहे। इसलिए आज की आवश्यकता यह है कि हम याद रखें मतदता हैं। किसी के खरीदे हुए बंधुआ मजदूर नहीं। हम शिक्षा लेकर मतदान नहीं करते। स्वयं अपने स्वामी हैं। जो नेता, जो राजनीतिक दल मुफ्तखोरी का भाषणी आश्वासन देकर भूखे पेट को सब्ज़बाग़ दिखाकर वोट लेना चाहता है या लेता हे अब उनको सीधे पाठ पढ़ाने का मौक़ा हैं उनसे सीधी बात करने का अत्यंत आवश्यक अवसर है। भारत सरकार हिम्मत करे। यह क़ानून बनना चाहिए कि जो वचन चुनाव से पूर्व जनता को दिए उसे पूरा किया जाए अन्यथा जो समझौता तोड़ने का और झूठ बोलने का दंड होता है वह दिया जाएं। कैसी विडंबना है जिस देश में आदर्श वाक्य यह है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उस देश में अब यह हो गया है वचन जाए पर सत्ता न जाए। आज देश का मतदाता बोलेगा तभी कल हमारा, हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा।▫▫

नज़ीर बनता बांग्लादेश

पिछले माह एक अच्छी ख़बर की बहुत चर्चा नहीं हुई। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को 'सबसे कम विकसित' देशों की श्रेणी से बाहर निकालने का फैसला किया है। उसकी अर्थव्यवस्था में तरक्की का मतलब है, उसे आगे कम इम्दाद की दरकार होगी। मसलन, उसने पिछली आधी सदी में चक्रवातीं तूफ़ानों से होने वाली मौतों में काफी ज़्यादा कमी कर ली है, जबकि वह जलवायु परिवर्तन के लिहाज़ से संवेदनशील मुल्कों में एक है। बांग्लादेश जैसे देश की यह नई उपलब्धि अगले साल हमें कहीं अधिक मानवीय मदद करनी होगी। 2022 में दुनियाभर में 27.4 करोड़ लोगों को तत्काल सहायता की दरकार होगी। मौजूदा वर्ष से यह 17 प्रतिशत अधिक हो सकती है और पिछले चार सालों में दोगुनी। अगर ये सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वह चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। संयुक्त राष्ट्र यह भी कहता है कि 43 देशों के 4.5 करोड़ लोगों पर भुखमरी का ख़तरा है और उनके लिए हमें 41 अरब डॉलर की मदद चाहिए। ये तमाम आवश्यकताएं संघर्ष, महामारी व मौसमी आपदाओं की वजह से पैदा होंगी। इथियोपिया से लेकर अफ़ग़ानिस्तान और म्यांमार तक के लोग प्रभावित होंगे। ज़ाहिर है, इनमें महिलाओं और लड़कियों का सर्वाधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में लैंगिक असमानताएं और सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि मानवीय मदद में जुटी तमाम संस्थाएं लैंगिक समानता पर ध्यान देने लगी हैं। यहां हमें फिर से बांग्लादेश की सफलता याद करनी चाहिए। चक्रवातों से निपटने संबंधी तैयारियों में उसेन 76,000 वॉलंटियर लगाए हैं, जिनमें से आधी महिलाएं हैं। ये वॉलंटियर मौसमी आपदाओं की चेतावनी भेजते हैं और लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम करते हैं। इनमें महिलाओं के रहने से मुश्किलों में फंसी औरतों की हिफाज़त करने में मदद मिली है। अगले वर्ष जब मानवीय ज़रूरतों के बढ़ने का अनुमान है, यह सुखद है कि 'दुनिया इन मुश्किलों से पार पाने के लिए एकजुट हो रही है।

बिभा त्रिपाठी

मानवाधिकार थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है

मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अस्तित्व में आने के 73वें साल में भी भारतीय संदर्भों में इसकी विवेचना उतनी ही प्रासंगिक है, जितना शुरू के सालों और दशकों में महसूस होती थी। इसकी वजह यह नहीं कि यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि यह कि जब भी मौक़ा आता है कोई विशेष राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का, तब वह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है मूल्यांकन का, विमर्श और वैचारिकता का। ताकि जान सकें कि हमने अभी तक क्या प्राप्त किया है? और ऐसा क्या है, जिसे अभी भी प्राप्त किया जाना बाकी है..? आज से कई वर्ष पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के.जी. बालाकृष्णन ने मानवाधिकार दिवस के मौके पर कहा था कि लगातार राज्य सरकार और उसके प्रवर्तन तंत्र द्वारा निरंतर ऐसे प्रगतिशील प्रयास किए जा रहे हैं, जो मानवाधिकारों का संरक्षण कर रहे है और विभिन्न कार्य विधियों का निरीक्षण हो रहा है। ऐसी सामाजिक कुरीतियों और प्रथाएं चलन से बाहर हो रही हैं, जिन्हें मानवीय गरिमा का विरोध पाया जाता रहा है। फिर भी बहुत कुछ ऐसा है, जिसे किया और पाया जाना अभी बाकी है।

मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जहां मानव परिसर के समस्त सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा तथा उनके सम्मान और अधिकारों की मान्यता, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार बना, वहीं बाद में यह अनुभव किया गया कि इसमें उल्लिखित एक से तीस अनुच्छेदों में जिन अधिकारों को संरक्षित और संवर्धित करने की बात कही गई है, इन सबके लिए क्रमश: विशिष्ट घोषणा पत्र अभिसमय, प्रसंविदाएं, ऐच्छिक संदेशाचार, नियमावलियां और मार्ग दर्शिकाएं भी बनाई गईं ताकि उनको विशिष्ट रूप से हस्ताक्षरित और अंगीकृत करने वाले राज्य पक्षकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सके कि वह अपने राज्य में इस बाबत विधियां बनाएं और सभी मनुष्यों के मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए यथोचित प्रयास करें।

पर जब भी राज्य विशेष के संदर्भ में मानवाधिकारों की बात की जाती है तो प्रश्न उठता है कि राज्य के विभिन्न अभिकरणों का, जिसे मूल रूप से प्रवर्तन तंत्र कहा जाता है, उनके द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है,? क्या खामियां? क्या सीमाएं हैं? क्या परेशानियां हैं? और किस प्रकार उन्हें दूर किया जा सकता है? और क्या समय के साथ यह भी महसूस किया गया कि कुछ नए मानवाधिकारों को भी मान्यता देने की आवश्यकता है? क्या कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जो अब तक अनछुए हैं? क्या मानवाधिकारों की इस लंबी विकास यात्रा में कुछ ऐसे भी पड़ाव हैं, जहां विभिन्न मानवाधिकारों के बीच ही एक संघर्ष की स्थिति बन गई है।

जिम्मेदारी और जवाबदेही मात्र शब्द नहीं, बल्कि वह बोध है, जिसका अभाव होने पर हर मानव अमानव है और हर संस्था अमानवीय है। विश्वास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास पर खरे उतरने का सच्चा प्रयास। न्याय की संकल्पना को यथार्थवादी धरातल पर पहुंचाने के लिए समग्र प्रयास और समेकित पहल की आवश्यकता है। इसकी पुरजोर वकालत वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने संविधान दिवस के मौके पर की थी। उन्होंने न्याय प्रादाताओं पर होने वाले हालिया आक्रमणों पर भी चिंता ज़ाहिर की। अब तक जहां केवल मीडिया, विशेषकर सोशल मीडिया, आक्रामक रहता था, वहीं अब न्यायाधीश पर होने वाले शारीरिक हमले गंभीर विवेचना का विषय बन गए हैं।

ऐसी महिलाएं जिन पर माओवादियों के साथ होने का आरोप लगा कर गिरफ्तार किया जाता है, उनको पुलिस हिरासत में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, उनका यौन शोषण होता है और कई सालों बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी भी कर दिया जाता है। उनके मानवाधिकारों का क्या हासिल है? यह एक गंभीर प्रश्न है।

बात जब विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन क़ैदियों की होती है और जहां तक एक ओर मानवाधिकार आयोग की यह पहल की विधि के छात्रों के बीच सार्वजनिक सेवा की भावना को बढ़ावा देकर विधिक सहायता प्रणाली के माध्यम से दिल्ली में क़ैदियों को न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए आरंभ की गई प्रायोगिक परियोजना एक राहत भरी ख़बर बनती है, वहीं जेलों में बंद विचाराधीन क़ैदियों या दूसरे क़ैदियों के मानवाधिकारों से इतर कुछ और गंभीर प्रश्न उठते हैं।

मसलन, उन पर निर्भर रहने वाले बच्चों के मानवाधिकारों का सवाल, जो बिना किसी ग़लती के अपने आरोपित माता पिता के क़ैद में जाने मात्र से महरूम हो गए हैं अपने मौलिक और स्वाभाविक मानवाधिकारों से। कैसे हो उनका संरक्षण? कौन सी नीति बने उनके लिए? यह प्रश्न गंभीर है और विचारणीय भी।

देश की विभिन्न जेल आचार संहिताएं जहां इस बात की व्यवस्था करती है कि किसी महिला के गंदी होने की स्थिति में उसके बच्चे छह वर्ष की आयु तक उसके साथ रह सकते हैं, वह प्रावधान एक मानवाधिकार का संरक्षण है, जो अन्य मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है। कानून सात वर्ष से ऊपर के बालकों के अभियोजन, विचारण और निरुद्धि के लिए विशेष प्रावधान करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि किशोरवय के किसी बालम को वयस्क अपराधियों की संगति में न रखा जाए। वहीं इस बात के पुख़्ता प्रमाण होने के बाद भी कि बच्चों की सीखने की क्षमता का सर्वाधिक विकास उनके गर्भ में आने की अवधि में से एक हजार दिनों तक होता है, छह वर्ष तक महिला जेल में अपनी मां और अन्य महिला क़ैदियों की संगति में रखना कितना प्रासंगिक है?

यहां इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी कि मानवाधिकारों की चयनात्मक विवेचना न की जाए और यह कहना कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तब होता है जब उन्हें राजनीति और राजनीतिक लाभ हानि के चश्मे से देखा जाता है महत्वपूर्ण है। इसी अवसर पर मानवाधिकार आयोग के हवाले से यह जानकारी दी जाती है कि 1993 में स्थापित आयोग अपनी स्थापना के 28 वर्ष पूरे होने तक बीस लाख से अधिक मामलों का निपटारा कर चुका है और 205 करोड़ से अधिक का भुगतान मौद्रिक राहत के रूप में किया जा चुका है। पर अपने योगदान पर गर्व करते आयोग का खुद को एक दंत विहीन शेर की संज्ञा देना भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा मानवाधिकार के जो मुद्दे उठाए गए, उनमें से कुछ का ज़िक्र प्रासंगिक है। जैसे, लोगों को सस्ती कीमत पर त्वरित न्याय के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक नीतियां, पुलिस जांच प्रणाली को मज़बूत करना, ग़रीबों को सस्ती कीमतों पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी दवाओं और टीकों के पेटेंट धारकों के अधिकारों के बजाय जीवन के अधिकार को महत्व दिया जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस वर्ष मानवाधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर छह अध्ययन कराए जाने हैं, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की खाद्य सुरक्षा, बच्चों के साइबर शोषण का विस्तार और कार्यबल में महिलाओं की गिरती भागीदारी तथा एलजीबीटी समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन का विषय प्रमुखता से लिया गया है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मानवाधिकारों की इस लंबी यात्रा में कुछ मिला है और कुछ बाकी है, यानि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। सभी के और समस्त मानवाधिकारों के बीस संतुलन, संवर्धन और संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मज़बूत रहनी चाहिए। ❑❑

इस्राईल-फलस्तीन सीधी वार्ता का समर्थन करेगा भारत : तिरुमूर्ति

न्यूयार्क : संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि इस्राईल और फलस्तीन की सुरक्षा चिंताओं को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में फलस्तीन पर कहा कि दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में बताया कि तीस वर्ष पहले विश्व बिरादरी ने मैड्रिड शांति सम्मेलन के माध्यम से इस्राईल-फलस्तीन के बीच वार्ता का एक रास्ता बनाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच के विवाद को दूर करने के लिए अब भी इस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत है और भारत इसका समर्थन करने को तैयार है। तिरुमूर्ति ने कहा, यूएनएससी द्वारा 2323 संकल्प द्वि-राष्ट्र विवाद को सुलझाने की पुष्टि के लिए अपनाया गया था, जो हिंसा रोकने की पैरवी करता है।

ख़ास ख़बरें

चीन ने अमरीकी अफ़सरों पर प्रतिबंध लगाए

बीजिंग : चीन ने अमेरिकी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सरकार आयोग के चार सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बीजिंग ने देश के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर चीनी अधिकारियों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में यह क़दम उठाया है। ये कदम शिनजियांग मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं। वाशिंगटन ने संबंधित क्षेत्र से आयात पर प्रतिबंध लगाया दिया है।

महारानी ने पारंपरिक क्रिसमस योजना रद्द की

लंदन : ब्रिटेन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के बीच महारानी ऐलिजाबेथ द्वितीय को पूर्वी इंग्लैंड के नॉरफोक में अपने सैंड्रिगम एस्टेट पर पारंपरिक क्रिसमस योजना छोड़नी पड़ी है और वह विंडसर पैलेस में ही रहेंगी। उन्होंने सैंड्रिगम की यात्रा रद्द करने का फैसला किया जिसे बकिंघम पैलेस ने 'व्यक्तिगत निर्णय क़रार दिया है। दरअसल क्रिसमस की सुबह को राजपरिवार के सदस्य क्रिसमस मनाने के लिए वहां एकत्र होते है।

यूक्रेन को लेकर अमेरिका- रूस में तनाव, ब्लिंकन ने चेताया

वाशिंगटन : यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। एक ओर, अमेरिका ने लिथुआनिया सरकार को 12.5 करोड़ डॉलर की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की बिक्री को मंज़ूरी दे दी है वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि यदि यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस आक्रामकता दिखाता है तो इसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे।

भारतीय तीर्थयात्रियों ने वीज़ा की संख्या बढ़ाने को कहा

लाहौर : भारत से 87 हिन्दू तीर्थयात्रियों का जत्था लव मंदिर पहुंचा और दर्शन के बाद इमरान ख़ान सरकार से अनुरोध किया कि वह भारतीयों के लिए वीज़ा की संख्या बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा संख्या में वहां से और तीर्थयात्री धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें। हिन्दू देवता भगवान राम के पुत्र लव के लिए बना यह मंदिर लाहौर किले में स्थित है। पुरानी कथाओं के अनुसार, लाहौर का नाम लव के नाम पर ही पड़ा है। प्रशासन ने मंदिर की मरम्मत आदि 2018 में पूरा किया था।

इंसान की तहक़ीक़ व रिसर्च अल्लाह की मख़्लूक़ात की गिनती करने में असहाय

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा अहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और फिर हमें ईमान अता किया। इंसान बनाकर परवरदिगार ने हमें दूसरी सारी मख़्लूक़ात से अफ़ज़ल किया और अहम व आला मक़ाम से नवाज़ा! अल्लाह तआला ने इस दुनिया में इस क़दर मख़्लूकात को पैदा किया है कि उन्हें गिनना मुश्किल है, आज जबकि साइंस ने आश्चर्यचकित तरक्की कर ली है, और आज के लोगों ने रिसर्च व तहक़ीक़ के मैदान को बड़ी सीमा तक विस्तृत कर लिया है, मगर इसके बावजूद अभी भी इंसान की तहक़ीक़ व रिसर्च अल्लाह की मख़्लूकात की गिनती करने में असहाय है यानि इंसान को अल्लाह की मख़्लूकात की सही संख्या के बारे में ज्ञान नहीं इतनी अधिक मख़्लूक़ात में जिस मख़्लूक को सबसे उच्च स्थान दिया गया हो उसकी अज़्मत का क्या ठिकाना हो सकता है? इस तौर पर इंसान की महत्ता व अज़्मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया ''और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूं'') तो फरिश्ते कहने लगे ''क्या आप ज़मीन में ऐसी मख़्लूक़ को पैदा करने वाले हैं जो आपस में झगड़े और खूं रेज़ी करे और हम तो आपकी तकदीस बयान करते हैं) अल्लाह तआला ने फरमाया ''यकीनन मैं अधिक जानने वाला हूं जो तुम नहीं जानते।'' कुरआन मजीद की इन आयतों से इंसान के उच्च स्तरीय स्थान का पता चलता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को इतना अज़ीम स्थान देकर यूँ ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इसके लिए एक उद्देश्य भी निर्धारित कर दिया कि इंसान की तख़्लीक बेवजह नहीं बल्कि इसके पीछे एक अज़ीम मक़सद कारफरमा है। इस अज़ीम मक़सद के बारे में अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया ''मैंने जिन्नात व इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।

इबादत को इंसान का मक़सद निर्धारित करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत का पूरा एक निज़ाम पेश किया ताकि इंसान अपने मक़सद की तरफ मुकम्मल तौर से गामज़न हो और वह अपने माबूद हक़ीक़ी की पूरे तौर से इबादत करें। दिनभर में पांच वक़्त की नमाज़ें रमज़ानुल मुबारक के रोज़ें, सालभर में साहबे निसाब होने पर ज़कात की अदायगी और इस्तआत की स्थिति में ज़िन्दगी में एक बार हज बैतुल्ला की अदायगी फ़र्ज़ की गयी।

ग़ौर करने की बात है कि इन चारों अहम इबादतों ने इबादत के सारे पहलुओं का अहाता कर लिया। दिनभर में पांच वक्त की नमाज़ों से जिसमानी इबादत का मक़सद हासिल हुआ, पूरे माह रमज़ान के रोज़ों से रूहानी मक़सद हासिल हुआ, ज़कात की अदायगी से माल ऐतबार से इबादत का फ़र्ज़ अंजाम दिया गया और हज बैतुल्लाह करने से जिस्मानी, रूहानी और माली का फरीज़ा अंजाम पाया, गोया इबादत के लिहाज़ से इंसानी ज़िन्दगी का अहाता कर लिया गया ताकि इंसान सम्पूर्ण तौर पर अपने मक़सद को प्राप्त करने वाला रहे और वह किसी भी वक्त या किसी भी ऐतबार से अपने मक़सद हक़ीक़ी को न भूले। इबादत की महत्ता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस्लाम के पांच मूलभूत अरकान में से पहले रुक्न का संबंध अकीदा ए तौहीद व रिसालत से है बाकी चारों अरकान इबादत से संबंधित हैं।

इन अरकान को इस्लाम के मूलभूत सतून कहा गया है यानि अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी से भी ग़ाफिल होता है और इसको तर्क करता है गोया वह इस्लाम के मूलभूत सतून को ढाने का इरतकाब करता है।

ज़कात की फर्ज़िअत कुरआन करीम से साबित है। कुरआन मजीद में ज़कात की अदायगी के बारे में विभिन्न स्थानों पर ताकीद की गयी है उदाहरणार्थ एक जगह फरमाया गया ''उसने पहले ही से तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इसी काम के दृष्टिगत ताकि रसूल तुम पर गवाह बनें और तुम लोगों पर गवाह बनो बस नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह से संबंध मज़बूत रखो (सूरह अल हज-78) इस आयत में नमाज़ की अकामत ज़कात की अदायगी और अल्लाह से मज़बूत संबंध की ताकीद की गयी है। इसके अलावा भी कुरआन करीम में विभिन्न स्थानों पर ज़कात की अदायगी का आदेश किया गया है। आमतौर से जहां नमाज़ के क़याम के सिलसिले में फरमाया गया है वहीं ज़कात की अदायगी के बारे में भी ताकीद की गयी है। कुरआन मजीद की बहुत सी आयतों में जिस तफ़्सील के साथ ज़कात का ज़िक्र किया गया है उससे मालूम होता है कि ज़कात अत्याधिक महत्वपूर्ण इबादत है।

यह ज़कात देने वाले पर अल्लाह का कितना बड़ा करम होगा कि अल्लाह तआला ज़कात देने वाले शख़्स को जहन्नुम की आग से महफ़ूज़ रखेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है ''और जहन्नुम की आग से वह आदमी दूर रखा जाएगा जो अल्लाह से बहुत अधिक डरने वाला है जो दूसरे को सिर्फ इसलिए अपना माल देता है कि (इसका दिल बुख़्ल व हिर्स से) पाक हो जाए।'' इस आयत से मालूम होता है कि ज़कात एक अहम मक़सद तज़किया नफ़्स भी है।

ज़कात का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब भी हासिल होता है, इरशाद बारी है ''और इन्हीं देहातियों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह और यौमे आख़िर पर ईमान रखते हैं और जो कुछ (राहे खुदा में) खर्च करते हैं उसे अल्लाह के तकर्रुब और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का ज़रिआ बनाते हैं, सुन रखो कि यह ज़रूर उनके लिए अल्लाह के तकर्रुब का ज़रिया है और अल्लाह तआला ज़रूर उनको अपनी रहमत में दाख़िल फरमाएगा, बिना शक वह बड़ा ही बख़्शने वाला और बड़ा ही रहम फरमाने वाला है''।

ज़कात अदा करने पर जिस क़दर अज्र का वादा किया गया है, उसी तरह ज़कात अदा न करने पर भी सख़्त अज़ाब की भी ख़बर सुनायी गयी है, मौला ए करीम इरशाद फरमाता है ''और जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए, एक दिन आएगा कि इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दहकायी जाएगी और फिर उसी से इन लोगों की पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दाग़ा जाएगा (और कहा जाएगा) यह है वह खज़ाना जो तुम ने अपने लिए जमा कर रखा था लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मज़ा चखो।)

ज़कात के ज़रिए एक मक़सद यह हासिल होता है कि इसके ज़रिए ग़रीबों, नादारों, यतीमों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती है और उनकी दिल जोई होती है। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है और मोमनीन का मालों में मांगने वालो और नादारों का हक़ है। ज़कात अदा करने पर जिस कदर अज्र का वादा किया गया है, उसी तरह ज़कात अदा न करने पर भी सख़्त अज़ाब की भी ख़बर सुनाई गयी है, इसलिए ज़कात देते समय इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि ज़कात में बेहतरीन माल ख़र्च किया जाए, ऐसा न हो कि गला सड़ा माल फकीरों, ज़रूरतमंदों को दे दिया जाए। अल्लाह तआला ऐसा करने से रोकता है,

''और ऐसा न हो कि (अल्लाह के मार्ग में) देने के लिए बुरी चीज़ छांटने लगो।''

ज़कात पाक माल की दी जानी चाहिए, अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ''ऐ ईमान वालो! अल्लाह के रास्ते में अपनी पवित्र कमाई ख़र्च करो) रसूले खुदा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ''अल्लाह पाक है और वह सिर्फ वही सदक़ा क़बूल करता है जो पाक माल से दिया गया हो।

ज़कात किन लोगों को दी जानी चाहिए, अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, 'ज़कात का माल तो सिर्फ फकीरों के लिए है, मिसकीनों के लिए है या और जो लोग सदक़े के काम पर मामूर हैं इनके लिए है और जिनकी तालीफ कल्ब मतलूब हो उनके लिए और गुलामों को आज़ाद कराने में कर्ज़दारों की मदद करने में और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफ़िर नवाज़ी में एक फरीज़ा है अल्लाह की ओर से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना व बीना है)। सारे सहाबा निसाब (धन सम्पन्न) को चाहिए कि वह ज़कात की अदायगी में ज़र्रा बराबर भी ग़फ़लत से काम न लें जो साहिबे निसाब हैं वह खुशी खुशी ज़कात को अदा करके अज्र अज़ीम के मुस्तहिक बनें, अल्लाह तआला सारे मुसलमानों को पूरी पूरी ज़कात निकालने की तौफीक़ अता फरमाए (आमीन) ❏❏

नूरे कुरआन

(सूरा अल कुरैश नं॰ 106)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें 04 आयते हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

इसलिए कि कुरैश अभ्यस्त हो गये हैं, अर्थात् उनको जाड़े गर्मी की यात्रा की आदत पड़ गयी है तो उनको चाहिए इस घर (काबे) के पालनहार की बन्दगी करें जिसने उनको भूख में खाना दिया और भय से अमन दिया।

मक्के में अनाज आदि पैदा नहीं होता। इस कारण कुरैश की आदत थी कि सालभर में व्यापार के उद्देश्य से दो यात्रायें करते थे, जाड़ों में यमन की ओर, क्योंकि वह मुल्क गर्म है और गर्मियों में शाम की ओर जो ठंड और हरा-भरा देश है। लोग उनको हरम के रहने वाले और अल्लाह के घर के सेवक समझकर बड़ा सम्मान करते, उनकी सेवा करते और उनके जान-माल से कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे। इस प्रकार उनको बहुत लाभ होता। इसके बाद शांतिपूर्वक घर में बैठकर खाते और खिलाते थे। हरम के चारों तरफ लूट खसोट चोर डकैती का बाज़ार गर्म रहता था, लेकिन काबे के अदब से कोई चोर डाकू कुरैश पर हाथ साफ न करता था। इसी ईनाम को यहां याद दिलाया है कि इस घर के कारण तुमको रोज़ी और अमन चैन दिया। हाथी वालों के आक्रमण से सुरक्षित रखा। फिर इस घर वाले के उपासना क्यों नहीं करते और इसके रसूल को क्यों सताते हो। क्या यह कृतघ्नता नहीं। अगर दूसरी बातें नहीं समझ सकते, तो ऐसी खुली हुई वास्तविकता का समझना क्या कठिन है।

टिप्पणी :- काबा मक्का के शहर में अल्लाह का घर है, उसके चारों ओर कुछ किलोमीटर तक का क्षेत्र हरम कहलाता है, जिसमें काबे के समान स्वरूप न किसी जंगली जानवर का शिकार कर सकता है न उनको सताया जा सकता है, न किसी जंगली या स्वयं उगे हुये वृक्ष को काटा जा सकता है, न जानवरों को चराया जा सकता है।

(सूरा अल माऊन नं॰ 107)

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें 07 आयते हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

क्या आपने उस व्यक्त को देखा जो इंसाफ़ होने को झुठलाता है।

अर्थात् समझता है कि इंसाफ न होगा और अल्लाह की ओर से अच्छाई और बुराई का बदला भी न मिलेगा। कुछ लोगों ने दीन का अर्थ मिल्लत लिया है अर्थात् इस्लामी मिल्लत और सच्चे दीन को झुठलाता है। तात्पर्य यह है कि धर्म और मिल्लत उसके लिए कोई चीज़ नहीं।

और असहाय को खाना देने पर ताक़ीद नहीं करता (प्रोत्साहन नहीं देता)।

अर्थात् यतीम की सहायता और सद्भावना तो दूर की बात, उसके साथ कठोर हृदय और बुरा व्यवहार किया करता है।

उत्तर प्रदेश के चुनाव तय करेंगे राजनीतिक दलों की राष्ट्र

उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने यह दावा करते हुए अपनी विजय यात्रा शुरू कर दी है कि लोगों ने पहले ही भाजपा के लिए फातिहा लिख दिया है और समाजवादी पार्टी की वापसी अपरिहार्य है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हें, लोगों से मिल रही हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने और कांग्रेस को भाजपा के यूपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र विकल्प के रूप में पेश करने का आहवान कर रही हैं।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा नेता बैठकें कर रहे हैं, परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और दोहरे इंजन वाली सरकार के महत्व पर ज़ोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुफ्त में हिन्दुत्व की खुराक पिला रहे हैं। ग़रीबों के बीच मुफ्त राशन की योजना को मार्च 2022 तक (चुनाव खत्म होने तक) बढ़ा दिया गया है और स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता के खातों में वर्दी खरीदने के लिए पैसे भी जारी किए गए हैं।

यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों का भविष्य दांव पर है और उत्तर प्रदेश के चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में इनकी भूमिका तय करेंगे। भाजपा नेतृत्व ने इस कटु सत्य को स्वीकार किया है क्योंकि अमित शाह ने अपनी हालिया रैली के दौरान कहा था कि यदि आप 2024 में मोदी को सत्ता में वापस लाना चाहते हैं तो 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी को वोट दें। अगर भाजपा उत्तर प्रदेश हारती है तो मोदी सरकार राजनीतिक कमान खो देगी। हमले तेज़ होंगे और प्रधानमंत्री के हर फैसले को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी हार विपक्ष को उत्साहित करेगी और उन्हें उम्मीद देगी कि वे 2024 के आम चुनावों में भाजपा को पछाड़ सकते हैं।

प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए परिदृश्य अलग नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बहन-भाई की जोड़ी के नेतृत्व का भाग्य दांव पर है। पिछले डेढ़ दशक में पराजयों से पार्टी का आधार कमज़ोर हुआ है। दलित, मुस्लिम और ऊंची जातियां, जो 80 के दशक के मध्य तक कांग्रेस के सर्वोत्कृष्ट समर्थन समूह थे, धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा में स्थानांतरित हो गए। 2014 तक 10 सालों तक भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार के शासन के बावजूद, केन्द्र में मनमोहन सिंह सरकार चलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर कांग्रेस की निर्भरता ने इन पार्टियों को कांग्रेस की कीमत पर उत्तर प्रदेश में लाभ उठाने का मौक़ा दिया। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए पार्टी को पुनर्जीवित करना एक कठिन काम होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 403 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 7 सीटें जीती थीं लेकिन अब उसके पास केवल 5 सदस्य रह गए हैं। मौजूदा हालात में दो दर्जन सीटजें जीतना भी पार्टी के लिए बड़ी जीत होगी। यह एक कठिन काम है और अगर प्रियंका परिणाम हासिल करने में विफल रहती हैं तो नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की आवाज़ उठने लगेगी।

यही हाल समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश यादव जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में हार उन्हें और गुमनामी में धकेल देगी और उनके नेतृत्व पर प्रश्न उठेंगे। सपा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव तथा 2017 के विधानसभा चुनाव हार गई थी, जो उसने अखिलेश के नेतृत्व में लड़े थे। इस बार अखिलेश के बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों के साथ गठबंधन करने की बजाय छोटे दलों के साथ जाने का फैसला किया है।

इससे पहले बसपा के पितामह कांशीराम ने अनुसूचित जाति और ओ.बी.सी. का एक बड़ा दलित बहुजन गठबंधन बनाया था। 1993 में प्रयोग के परिणाम सामने आए जब राम मंदिर आंदोलन के चरम पर भाजपा को हराने के लिए सपा और बसपा गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक साथ आए। 2007 में, सर्व समाज पर अपने ध्यान के माध्यम से मायावती अत्यंत पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहीं और अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया।

अखिलेश यादव ने दलितों व ओ.बी.सी. के सम्मान की रक्षा करने तथा सत्ता में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए डा. बी.आर. अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया के अनुयायियों को एक साथ आने का आहवान किया है। यह घोषणा एक योजना के तहत की गई है क्योंकि अन्य पिछड़ी जातियां (ओ.बी.सी.) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसी कि उन्होंने 2019 के आम चुनावों और 2017 के विधनसभा चुनावों में निभाई थी। भाजपा केवल इसलिए सत्ता में आई क्योंकि वह ओ.बी.सी. का अच्छा समर्थन हासिल करने में सफल रही क्योंकि उसने छोटे लेकिन जाति आधारित दलों के साथ प्रभावी गठबंधन किया था। चुनाव के इस संस्करण में अलिखेश यादव पहले ही ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एस.बी.एस.पी.) जैसी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। सेपा केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व वाले महान दल के साथ भी गठबंधन में है और पश्चिमी यूपी में इसने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन की घोषणा की है।

मायावती को दलितों के बीच जो समर्थन प्राप्त है उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। बसपा को बट्टे खाते मे डालना गलत होगा क्योंकि पार्टी 20 प्रतिशत से अधिक वोट बैंक के लिए प्रतिबद्ध हैं पार्टी ने राज्यभर में ब्राह्मण सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, लेकिन जिस तरह से विधायकों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता बसपा छोड़ सपा में शामिल हो रहे हैं, वह उसके कमज़ोर आधार को दर्शाता है। मायावती ने अभी अभियान शुरू नहीं किया है लेकिन एक बार शुरू होने पर उनके एक जिले से दूसरे जिले में जाने के बाद लोगों के उनके समर्थन में उतरने से इंकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर स्थिति क्या बनती कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, यह जनता तय करेगी। यूपी के इन चुनावों को महत्वपूर्ण यूं ही नहीं माना जाता क्योंकि इससे राष्ट्रीय राजनीति में हर पार्टी का स्थान तय होता है। ❑❑

मायावती की ऊहापोह ने बढ़ाई दलित मतदाताओं की बेचैनी

बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमो मायावती की ऊहापोह को लेकर उनके समर्थक दलितों में भी इस बार बेचैनी दिख रही है। बहनजी के नाम से लोकप्रिय मायावती अपने तीन दशक के सियासी जीवन के सबसे कठिन दौर का सामना कर रही है। भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों पार्टियां चुनावी जंग में पहले ही कूद पड़ी है। पर चुनावी पटल से बसपा अभी तक नदारद है। मायावती ने अभी तक तो अपनी एक भी रैली का ऐलान नहीं किया। उधर उनके नेताओं में पार्टी छोड़ने की भगदड़ दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली थीं। रितेश पांडे बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए तो उन्हें विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। उपचुनाव में यह सीट सपा ने जीत ली। बची 18 में से फिलहाल पार्टी की सदस्य संख्या विधनसभा में तीन रह गई हैं पिछले माह विधायक दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पार्टी छोड़ने के बाद जमाली की प्रतिक्रिया थी कि बसपा इस बार चुनावी मुक़ाबले में कहीं है ही नहीं। मुक़ाबला भाजपा और सपा के बीच ही है।

इस दयनीय स्थिति के पीछे वजह तो भाजपा के प्रति मायावती का लगातार नज़र आया नरम रवैया हैं पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 1993 का इतिहास दोहराते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। यह गठबंधन अपेक्षित नतीजे तो बेशक नहीं दे पाया था पर मायावती को इसका फायदा ही हुआ था। लोकसभा के 2014 के चुनाव में जहां उनका खाता भी नहीं खुल पाया था वहीं पिछले चुनाव में उन्हें दस सीटें मिल गई थीं, लेकिन चुनाव परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद मायावती ने सपा से गठबंधन यह कहकर तोड़ दिया था कि ऐसा करना उनकी भूल थी।

लोकसभा चुनाव के बाद से मायावती ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों के ख़िलाफ़ कोई आंदोलन तक नहीं किया न ही तीखी बयानबाज़ी की। इसके उलट वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमले करती रहीं। अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनना उनका मिशन होता तो विपक्ष के बजाय निशाने पर सत्ता पक्ष को रखती। लोकसभा में अपने दल के नेता कुंवर दानिश अली को हटाकर पहले श्याम सिंह यादव और रितेश पांडेय को उनकी जगह नेता बनाकर मायावती ने मुसलमानों और पिछड़ों को और नाराज़ किया था। मायावती के बारे में यह धारणा पिछड़ों और मुसलमानों में ही नहीं बल्कि दलितों में भी पनपने लगी है कि या तो भाजपा से उनका अनुराग है या वे डर रही है। डर अपने भाई आनंद की कंपनियों के ख़िलाफ़ चल रही आयकर और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केन्द्रीय एजेंसियों की जांच की फिलहाल सुस्त दिख रही।

वैसे भाजपा से मायावती का सारा विरोध अतीत में भी चुनाव पूर्व तक ही रहा। चुनाव के बाद शुरुआती तीन अवसरों पर तो वे सूबे की सत्ता के सिहांसन पर भाजपा की मदद से ही बैठी थीं। अलबत्ता 2007 में बहुजन के बजाय सर्वजन के समर्थन का उनका फार्मूला सफल हुआ था। विधान सभा की 403 सीटों में से 206 सीट जीतकर उन्होंने न केवल सूबे में अपने बूते पर सरकार बनाई थी बल्कि 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें जीतने के बाद तो वे प्रधानमंत्री पद का भी सपना देखने लगी थीं। बसपा ने इस चुनाव में नारा दिया था – ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। लेकिन 2014 के चुनावी नतीजे के उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया था।

मायावती का सियासी सफर 1984 में बसपा की स्थापना के साथ कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव से शुरू हुआ था। फिर वे बिजनौर और हरिद्वार लोकसभा सीट से उपचुनाव में भी सामने आई। पर सफलता पहली बार 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बिजनौर से मिली। इस बीच 1993 में सपा से तो 1996 में पार्टी ने कांग्रेस से विधानसभा चुनाव का समझौता भी किया। भाजपा के उभार ने न केवल उनसे अगड़े वोट बैंक को छीन लिया बल्कि अति पिछड़े वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। इसी दौरान लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दिकी, रामबीर उपाध्याय, रामअचल राजभर, बरखूराम वर्मा और बाबू सिंह कुश्वाहा जैसे पार्टी के तमाम कद्दावर नेता मायावती का साथ छोड़ गए। पुराने नेताओं में उनके साथ सतीश चन्द्र मिश्र ही बचे हैं। जिन्होंने पिछले दिनों ब्राह्मण सम्मेलन कर दलित वोट के साथ उन्हें जोड़ने का 2007 का सफल प्रयोग फिर दोहराना चाहा था। लेकिन उनके सम्मेलनों के प्रति ब्राह्मणों में कोई उत्सुकता नहीं दिखी तो वे भी ख़ामोश बैठ गए। फिलहाल मायावती का भविष्य भी इन्हीं चुनावों पर टिका हुआ है अगर पार्टी कुछ सफलता हासिल करती है तो ज़िन्दा रह सकता है, वर्ना उसके अस्तित्व पर ख़तरा मंडरा सकता है। ❑❑

विराट मामले में बोर्ड से ग़लती कहां हुई

विराट कोहली और रोहित शर्मा के संबंधों की खटास को लेकर दोनों भी यह गुत्थी और उलझती नज़र आ रही है। रोहित शर्मा को टी-20 का कप्तान बनाते समय ही विराट को इस बात का अहसास हो गया होगा कि देर सबेर वनडे की कप्तानी भी उनके हाथों से जाने वाली है। विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने से शायद ही किसी को एतराज़ होगा। आख़िर उनके ऊपर कोई भी आईसीसी ट्रॉफी न जीत पाने का ठप्पा लगा हुआ हे लेकिन इस मामले को जिस तरह से बीसीसीआई ने हैंडल किया, उससे यह गुत्थी ज़्यादा उलझी है।

चोटिल होने की वजह से दक्षिण अफ्रीकी दौरे की टैस्ट टीम से रोहित शर्मा के बाद इस मामले को जैसा मोड़ दिया गया, वह निश्चय ही ग़लत है। रोहित के टेस्ट टीम से हटने के बाद यह खबर हवा में तैरी कि विराट कोहली वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे और यह उन्होंने बीसीसीआई को बता दिया। सूत्रों के हवाले से चलाई गई इस खबर का मतलब यह निकाला गया कि विराट और रोहित एक दूसरे की कप्तानी में खेलने को तैयार नहीं हैं। सच्चाई का पता लगाए बग़ैर तमाम पूर्व खिलाड़ी प्रतिक्रिया भी देने लगे। बाद में विराट कोहली ने बताया कि उन्होंने वनडे सीरिज से हटने के लिए बीसीसीआई को लिखा ही नहीं। इससे लगता है कि बीसीसीआई से जुड़े किसी अन्य सूत्र ने जानबूझकर यह झूठी ख़बर उछाली।

विराट कोहली के यह कहने से कि टी-20 की कप्तानी छोड़ते समय किसी बोर्ड अधिकारी ने उनसे फैसले पर दोबारा सोचने को नहीं कहा था, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग गया है। उनके मुताबिक विराट को टी-20 की कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था, लकिन वह राज़ी नहीं हुए। इसलिए बीसीसीआई और चयनसमिति को उन्हें वनडे कप्तानी से हटाना पड़ा क्योंकि वनडे और टी-20 दोनों ही वाइट बॉल फारमैट से आते हैं सवाल यह है कि यदि बीसीसीआई और चयन समिति एक फारमैट एक कप्तान' के लॉजिक में विश्वास करता है तो रोहित को टी-20 का कप्तान बनाते समय ही वनडे का भी कप्तान क्यों नहीं बनाया गया..?

आमतौर पर माना जाता है कि बीसीसीआई के क़रार वाले खिलाड़ी उसके ख़िलाफ़ बयान नहीं दे सकते हैं लेकिन विराट ने कोई बयान तो दिया नहीं हैं दौरे पर रवाना होने से पहले अधिकृत संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि विराट से टी-20 कप्तानी न छोड़ने की बात पांच चयनकर्ताओ और तीन बीसीसीआई अधिकारियों के सामने की गई थी, लेकिन बोर्ड इस बारे में कोई बयान जारी करता है तो कप्तान झूठे साबित होंगे, जिसका टीम के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बीसीसीआई ने फिलहाल इस मामले को तूल न देने का फैसला किया है।

विराट कोहली 2014 में आस्ट्रेलियाई दौरे पर धोनी के कप्तानी छोड़ने पर टेस्ट कप्तान बने और 2017 में उन्हें तीनों प्रारूप का कप्तान बनाया गया यह वह दौर था, जब बीसीसीआई का संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति के हाथों में थी। इस दौर में विराट कोहली को फ्री हैंड दिया गया। धीरे-धीरे उनका क़द इतना बड़ा हो गया कि उनके फैसलों के आगे बीसीसीआई भी झुका नज़र आता था। उन्होंने कई मौक़ों पर मनमाने फैसले भी किए जिनकी आलोचना हुई।

बहरहाल, बीसीसीआई का इतिहास गवाह हे कि उसने हमेशा अपने को सर्वोपरि रखा है। इस कारण तमाम बार ताख के पत्तों को फेटने की तरह कप्तान बनाए और हटाए गए। उदाहरण के लिए आर.के. पटेल 1958 से 1960 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष

बाक़ी पेज 11 पर

2022 विंटर ओलिपिंक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं 'आरिफ़'

जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ ख़ान बीजिंग विंटर ओलिपिंक 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 31 वर्ष के आरिफ ने पिछले दिनों दुबई में क्वालिफायर अल्पाइन टिकट हासिल किया था। गुलमर्ग से सटे तंगमर्ग में पैतृक गांव में आरिफ़ के पिता मौ. यासिन ख़ान ने इसे दो दशक की कड़ी मेहनत का परिणाम कहा है। आरिफ ने पिता से स्कीइंग सीखी, जो कश्मीर के पहले स्की गाइड थे। यासिन 1980 से 2006 तक गुलमर्ग में स्की गाइड का काम करते थे। यासिन ने कहा 'चार वर्ष की आयु से ही आरिफ गुलमर्ग की ढलानों पर मेरे साथ जाता था। उसे स्कीइंग में बहुत रुचि थी। धीरे धीरे ये जुनून बन गया और उसने इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। यह ढलानों पर घंटों बिताता और बारीक से बारीक चीज़ सीखने की कोशिश करता है।' आरिफ ने 13 साल की आयु में चीन में विंटर गेम्स में सब जूनियर कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ल्ड चैम्पियनशिप सहित कई इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले वर्ष साउथ एशियन चैम्पियनशिप में उन्होंने दो गोल्ड भी जीते। यासिन ने बताया, 'आरिफ़ रोजाना छह घंटे ट्रेनिंग करता हैं पिछले 4 वर्ष में माइनस 20-25 डिग्री तापमान में ट्रेनिंग लेना शुरू कर ओलंपिक का टिकट हासिल किया। इस वर्ष वह फरवरी से ही ऑस्ट्रिया में ट्रेनिंग कर रहा था। इस वर्ष उसे अपनी शादी स्थगित करनी पड़ी, ताकि वह प्रशिक्षण ले सके और ओलिपिंक के लिए क्वालिफाई कर सके। यासीन ने कहा 'हमने सितंबर में उसकी शादी की योजना बनाई थी, लेकिन उसके प्रशिक्षण के कारण हमें इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा।' उन्होंने बताया 'स्की महंगा खेल है। उन्होंने बताया 'स्की महंगा खेल है। ऑस्ट्रिया में आरिफ को प्रतिदिन लगभग 21,000 रुपये खर्च करने पड़ते। इस में इस्तेमाल होने वाले उपकरण की कीमत भी लगभग 5 लाख रुपये होती है। एक जोड़ी स्की 85,000 से अधिक और सर्दियों के जूते की कीमत 45000 रुपये से अधिक है। वह पिछले ओलिपिंग के लिए भी क्वालिफाई कर लेता, लेकिन पैसों की कमी और कुछ दूसरे लॉजिस्टिक मुद्दों के करण ऐसा नहीं हो सका।' ❑❑

मधुमेह के इलाज में नए आयाम

मधुमेह के इलाज में बैरियैट्रिक सर्जरी के प्रभावी होने के इतने मज़बूत सबूत के बावजूद सर्जनों ने यह घोषणा करने से परहेज़ किया कि वे मधुमेह को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं।

पिछले सालों में भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी की सर्जरी करने की वजह से पूरे देश में सुर्खियों में आए मुम्बई के जाने माने बैरियैट्रिक सर्जन मुफ्फ्ज़ल लकड़ावाला ने कहा कि मधुमेह को क्योर (जड़ से ठीक कर देना) कर देने की जगह यह कहना चाहूंगा कि इस सर्जरी के बाद मधमेह लंबे समय के भाग खड़ी हाती है। इस सर्जरी से मधुमेह के इलाज पर सर्वानुमति बनाने के लिए एशिया का पहला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि इसमें दवा और इंसुलिन से मधुमेह को साधने वाले अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ग़ैर संक्रामक रोगों के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख दवा से मधुमेह का इलाज करने वाले डाक्टरों के ग्लोबल संगठन इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरशन के अध्यक्ष एवं मोटापा दूर करने के सर्जनों के इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष की उपस्थिति से साफ हो गया है कि भारत में भी मधुमेह के इलाज का नया युग दस्तक दे रहा है। डॉ. लकड़वाला की तरह ही बैरियैट्रिक सर्जरी के एशिया के चंद विशेषज्ञों में शुमार सर गंगाराम अस्पताल के बैरियैट्रिक एवं मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रमुख डॉ. प्रवीण भाटिया ने कहा कि मधुमेह को लेकर अब मेडिसिन और सर्जरी में कोई मतभेद नहीं रह गया यानि अब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट (डायबेटालॉजिस्ट) खुद ही उन मरीज़ों को सर्जरी करवाने की सलाह देंगे जिनका शुगर नियंत्रित है [यानि जिन्हें अपनी दवा एवं इंसुलिन की मात्रा लगातार बढ़ानी पड़ रही है] इस सर्वानुमति के बाद 30 बीएमआई (मोटापा नापने की इकाई) वाले मधमेह के मरीज़ भी सर्जरी का सहारा ले सकेंगे। प्राइमस अस्पताल के बैरियैट्रिक सर्जन ने कहा कि दुनिया की मधुमेह की राजधानी बन गए इस देश में बैरियैट्रिक सर्जरी की मांग में भारी इज़ाफा होना तय है। इस बारे में जल्द ही गाइड लाइंस भी पेश हो जाएंगी। इस सर्जरी की बढ़ती मांग का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेंटर फॉर ओबेसिटी एवं डायबिटीज सर्जरी के संस्थापक को मुम्बई में ही सांस लेने की फुर्सत नहीं है।

मतलब वह दिन दूर नहीं जब मधुमेह मेडिकल रोग न होकर सर्जिकल रोग हो जाएगा। ज़ाहिर है इससे मधुमेह को नियंत्रित करने की एलोपैथी आयुर्वेदिक दवाओं एवं इंसुलिन की खपत में भारी कमी भी आएगी। इस देश में मधुमेह के इलाज का एक बहुत बड़ा बाजार है। इसीलिए टीवी चैनलों पर नकली असली आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रचार की भरमार हो गई है। तमाम रोगों की 'मां' मधुमेह से छुटकारे की लोगों में भारी छटपटाहट रहती है इसलिए किसी दवा के भी कारगर होने का दावा सुनाई पड़ जाए तो वे उसके पीछे भागते हैं लेकिन बैरियैट्रिक सर्जन अब मधुमेह के इलाज के ट्रेंड में अमूल चूल परिवर्तन ला देगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहा।

विशेषज्ञों के अनुसार इसकी वजह यह है कि मधुमेह होने पर आंख, दिल, किडनी, लीवर से लेकर पांव और मर्दानगी व सेक्स लाइफ तक पर भारी ख़तरा उत्पन्न हो जाता है। करीब 15 प्रतिशत मरीजों की आंखें चली जाती हैं। 40 हज़ार से अधिक लोगों को अपनी टांगें कटानी पड़ती हैं। मधुमेह के मरीज़ दिल, किडनी, लीवर के भी मरीज़ बन रहे हैं। मधुमेह के ठीक पहले की स्थिति भी इन अंगों के लिए घातक साबित हो रही है। इसलिए मरीज़ों में मधुमेह से पूरी तरह से छुटकारे की छटपटाहट लाज़िमी है। अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं है जो मधुमेह को पूरी तरह से ठीक कर दे। लेकिन बैरियैट्रिक सर्जरी ने यह संभव कर दिखाया है। यह वैसे मूलरूप से मोटापा कम करने की सर्जरी थी लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मधुमेह की सर्जरी बन जाएगी। गडकरी इस सर्जरी से इसलिए चमतकृत नहीं है कि इससे वे छरहरे होने लगे है बल्कि वे इसलिए बेहद खुश हैं कि इसने इनका मधुमेह और उच्च रक्तचाप ठीक कर दिया है। उनको अब दवा और इंसुलिन से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है।

दरअसल, गडकरी ने मोटापा कम करने के लिए नहीं मधुमेह के इलाज के लिए यह सर्जरी कराई थी।

बैरियैट्रिक सर्जरी के बाद कुपोषण का सवाल उठता है। इस सर्जरी से भूख नहीं के बराबर रह जाती है। थोड़ा खाते ही लगता है कि जैसे पेट भर गया हो। शरीर में विटामिन और प्रोटीन व अन्य मिनरलों की कमी हो सकती है लेकिन सर्जरी के बाद मिलने वाली सुरक्षा को देखते हुए मरीज़ थोड़े कुपोषण के लिए भी तैयार हो रहे हैं। चूंकि मधुमेह के 80 प्रतिशत से ज़्यादा मरीज़ मोटे होते हैं इसलिए बैरियैट्रिक सर्जरी के मधुमेह का पहला इलाज होने में अब कोई संदेह नहीं रह गया है। अब बैरियैट्रिक सर्जरी की ऐसी तकनीक भी आ गई है जिससे कुपोषण का खतरा भी कम हो गया है। इस सर्जरी के बाद जितनी तेजी से वजन घटता है उतनी ही तेजी से शुगर नियंत्रित करने की दवा भी कम होती चली जाती है और अंत में दवा लेने की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। बैरियैट्रिक सर्जरी में रोबोट से जुड़ पाने से इलाज की गुणवत्ता में भी ख़ासा इज़ाफ़ा होने की संभावना है। डॉ. भाटिया ने रोबोट से यह सर्जरी बहुत पहले शुरू कर दी है। उन्होंने देश में रोबॉट से सबसे अधिक बैरियैट्रिक सर्जरी की है। विराट कोहली के भाई, गडकरी एवं अदनाम सामी जैसे उदाहरणों ने भी इस सर्जरी को विश्वसनीयता प्रदान की है। अमेरिका सहित अन्य देशों में यह सर्जरी पहले से ही मधुमेह का पहला इलाज बन गया है। ❑❑

शेष.... भारत-अफग़ान ....

लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है – धरती एक ही परिवार है। यही वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। दुनिया गवाह है कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने न केवल पड़ोसी देशों को बल्कि ब्राज़ील जैसे दुनिया के कई देशों को कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई थी। भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देशों की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हमेशा मदद की है। भारत में अफग़ानिस्तान के राजदूत फरीद मामुल्दज़ई ने टवीट कर भारत को ध न्यवाद करते हुए लिखा है –''अपने उपकार करने वालों के साथ जो साथ ता बरतता है, उसकी तारीफ नहीं है, महात्मा तो वह है जो अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करे। इस कठिन समय में अफग़ानिस्तान के बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारत को धन्यवाद।

भारत ने अफग़ानिसतान को सहायता भेजकर राजनयिक खिड़कियां तो खोल दीं हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अफग़ानिस्तान में भारतीय निवेश का भविष्य क्या है? 2001 में अमेरिका द्वारा अफग़ानिस्तान में तालिबान शासन के ख़ात्मे के बाद भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में बुनियादी ढांचे और मानवीय सहायता पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। राजमार्गों के निर्माणा से लेकर भोजन के परिवहन और स्कूलों के निर्माण तक भारत ने समय-समय पर धन का निवेश करते हुए विध्वंस का शिकार हुए देश के पुनर्निमाण में मदद की है। अब वहां भारतीय परियोजनाओं के लिए नियमित रख रखाव की जरूरत होगी और ये केवल अनुकूल वातावरण में ही जारी रह सकती है। वहां चल रही सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक राजमार्ग का निर्माण भी शामिल है। जो भारत को अफग़ानिस्तान के साथ जोड़ेगा। भारत के लिए यह सड़क सम्पर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भारत को अपने क्षेत्र में अफग़ानिस्तान में राजनीतिक और लोकतांत्रिक परिवतन भी शामिल था। भारत यही चाहता है कि अफग़ानिस्तान में समावेशी शासन व्यवस्था हो। भारत केवल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत विरोधी आतंकीवादी अफग़ानिस्तान से भारतीय धरती पर हमले शुरू न कर दे। भारत इस इलाके में भारत विरोध ी गतिविधियों में लिप्त ग्रुपों को समर्थन देने का पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है और पाकिस्तान की अफग़ानिस्तान में भूमिका पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत को अभी इंतज़ार करना होगा कि तालिबान शासन क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तालिबान ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मानवीय मदद और विकास परियोजनाओं के लिए भारत का स्वागत है। तालिबान यह भी स्वीकार करता है कि पिछले 20 सालों में भारत की तीन बिलियन डॉलर से अधिक के प्रोजेक्टस बहुत फायदेमंद रहे हैं। देखना होगा कि इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे अफग़ानिस्तान का तालिबान शासन क्या रुख़ अपनाता है। इस बात की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए कि क्या भारत तालिबान के साथ काम कर सकता है या नहीं या कोई बीच का सकारात्मक रास्ता भी तलाश करने की ओर क़दम बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ❑❑

शेष.... वर्ष 2021 में कोरोना ने.....

अस्पताल में अत्याधुनिक आटोमेटेट ड्राई केमेस्ट्री लैब का शुभारंभ हुआ, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 50 हजार सैंपल जांच करने की है।

केन्द्र सरकार के सफदरजंग, आरएमएल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रविवार की ओपीडी शुरू हुई। एम्स में भी दिल की सर्जरी करा चुके मरीज़ों के फॉलोअप जांच के लिए रविवार को विशेष क्लीनिक शुरू किया गया। सफदरजंग अस्पताल में 44 बेड का मेक शिफ्ट वार्ड शुरू किया गया।

एम्स में ब्लड व पैथोलॉजी जांच, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड जांच का समय बढ़ा दिया गया है। इसलिए विभिन्न ब्लड जांच, एक्स-रे व अल्ट्रा साउंड जांच में वेटिंग ख़त्म हो गई है।

शेष.... हमारा सारा काम....

एक मौक़ा देना तो बनता है।

प्रश्नः- पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं की सभाएं हो रही हैं हर वर्ग से मुलाक़ात की जा रही है, किस तरह की योजनाएं, हैं आपकी, पंजाब जानना चाहता है..?

उत्तरः- पंजाब कांग्रेस से धोखा खा चुका है। उससे पहले अकाली और भाजपा से धोखा खाया था। दिल्ली में पंजाब के लोगों ने देखा है कि केजरीवाल सरकार ने बड़े-बड़े काम करके दिखाए हैं। पंजाब में यही कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में किया है वह यहां भी करके दिखाइए। हम भी पंजाब से यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम करने की राजनीति करती है। ईमानदारी की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी वह पैसा जो जनता के काम आना चाहिए और टैक्स के रूप में आना चाहिए उसे खनन माफिया के पास नहीं जाने देती। इस तरह का काम, पंजाब में भी किया जाएगा और ग़ैर कानूनी गतिविधियों को बंद करवाकर टैक्स जमा कराया जाएगा। इस तरह के काम करके पंजाब की अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया जाएगा। व्यापारी वर्ग को मज़बूत किया जाएगा। जो दिल्ली के व्यापारियों के लिए किया, वह पंजाब के लिए भी किया जाएगा। व्यापारी खुशहाल होगा तो टैक्स भी बढ़ेगा और लोगों के लिए योजनाओं पर काम भी किया जाएगा। ❑❑

शेष.... प्रथम पृष्ठ

मित्रों, परिजनों, किसी निजी संस्था या निगम द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देकर अथवा किसी अन्य माध्यम से किए जाने वाले ख़र्च को प्रत्याशी के चुनावी ख़र्च में जोड़ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च को चुनावी खर्च में शामिल करने का आदेश दिया था। किन्तु यहां भी सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर इस निर्णय को पलट दिया।

केन्द्र सरकार ने साल 2018 में चुनावी बांड योजना की अधिसूचना जारी की थी। इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद दान के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2018 के बजट में राजनीतिक दलों को विदेशी स्रोतों से चंदा/अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। उसी अनुरूप विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में संशोधन कर दिया गया। इस संशोधन के तहत विदेशी कंपनी की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है। इसके माध्यम से कंपनियों के लिए राजनीतिक चंदे पर लगी अधिकतम सीमा हटा ली गई। इससे पूर्व कंपनियों अपने तीन वर्ष के शुद्ध लाभ का अधिकतम साढ़े सात प्रतिशत हिस्सा ही राजनीतिक चंदे के तौर पर दे सकती थीं। साथ ही, उन्हें यह बताने की शर्त से भी छूट मिल गई कि उन्होंने किस दल को कितना चंदा दिया है।

भारत के लोकतंत्र को धन-बल के प्रभाव से कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बुरा और परोक्ष प्रभाव है भ्रष्टाचार में वृद्धि या कहें कि भ्रष्टाचार को अघोषित मान्यता मिलना। करोड़ों ख़र्च कर चुनाव जीतने वाले जनसेवा के भाव से तो आते नहीं हैं। उनका प्राथमिक मकसद होता है अपने खर्च हुए रुपए बटोरना और अगले चुनाव की लागत वसूलना। दूसरा नुकसान यह है कि अपराधि यों को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। राजनीति के माध्यम से असामाजिक तत्व और अपराधी 'माननीय' बन जाते हैं और जिससे उन्हें क़ानून और प्रशासन से प्राथमिकता मिल जाती है और इसका प्रभाव वे अपना वर्चस्व बढ़ाने में करते हैं। वर्ष 2009 के चुनाव में आपराधिक मामलों के आरोपी उनतीस प्रतिशत उम्मीदवार विजयी रहे। 2014 में यह आंकड़ा चौबीस प्रतिशत था और 2019 में बढ़कर तियालीस प्रतिशत हो गया था।

पिछले दो-तीन दशकों से भारतीय चुनावी परिदृश्य में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के निर्वाचित होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। इन दोनों तथ्यों के बीच एक प्रकार संबंध प्रतीत होता है और यह गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए सबसे बड़ा दोष राजनीतिक दलों का है, क्योंकि जब तक वे आर्थिक सक्षमता एवं बाहुबल के प्रभाव के बजाय व्यक्ति की योग्यता को प्रत्याशी बनने के लिए अधिमान नहीं देंगे, तब तक ये परिस्थितियां यथावत बनी रहेंगी। किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को उसकी बेहतर वित्तीय स्थिति के कारण दूसरों से अधिक लाभ नहीं मिलना चाहिए।' हालांकि वर्तमान में यह उम्मीद पूरी होती तो नहीं दिखती। फिलहाल चुनावी खर्च प्रत्येक चुनाव में अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, एक तरह से कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी कि राजनीतिक दल अपनी सहूलियत और चुनाव जीतने के लिए जो जो पैंतरे आज़माते हैं उनके लिए चुनावी खर्च कोई अहमियत ही नहीं रखता। उन्हें पता है कि जीत जाने के बाद जीतना खर्च हुआ है पांच वर्ष में उसकी तो पूर्ति कर ही लेंगे बल्कि अगले चुनाव का ख़र्च भी निकाल लेंगे। ❑❑

शेष.... विराट मामले में ....

रहे थे। उनके कार्यकाल में एक साल में पांच कप्तान बना दिए गए थे। ये कप्तान थे - पॉली उमरीगर, गुलाम अली, वीनू माकंड, हेमू अधिकारी और डी.के. गायकवाड।

भारत का 1971 का ऐतिहासिक वेस्टइंडीज दौरा खेल प्रेमियों को अच्छे से याद होगा इस दौरे पर भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ उसके घर में पहली बार सीरीज़ जीती थी। इस दौरे के लिए कप्तान का चयन जिस तरह से हुआ, वह गज़ब ही था। मंसूर अली ख़ां पटौदी का कप्तान के तौर पर जाना लगभग तय था लेकिन आखिरी पलों में कप्तान बनाया गया अजित वाडेकर को। वाडेकर अपनी पत्नी के साथ सब्जी खरीदने गए थे। घर लौटने पर पत्रकारों का जमावड़ा देखा और तब पूछने पर मालूम हुआ कि उन्हें कप्तान बना दिया गया है। वर्ष 1975 में तो फारुख़ इंजीनियर टॉस के लिए जाने ही वाले थे, पर उन्हें सूचना दी गई कि वेंकट राघवन को कप्तान बना दिया गया है।

ऐसी घटनाए सिर्फ भारत में ही नहीं होतीं। पाकिस्तान में आपसी राजनीति की वजह से कई कप्तानों को पद गंवाना पड़ा है। यहां तो यह आलम रहा है कि कराची काप्तान होने पर लाहौर लॉबी पीछे पड़ जाती थी और लाहौर का कप्तान बनने पर कराची लॉबी उसे हटवाने में लग जाती थी। आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में ज़रूर पारदर्शिता है। फिर भी टीम पेन के मामले में क्रिकेट आस्ट्रेलिया की ग़लती उजागर हुई है। बोर्ड इस बात से वाक़िफ़ था कि टिम पेन लड़की को भद्दे संदेश लिख रहे हैं फिर भी उन्हें समय रहते कप्तानी से हटाने का फैसला नहीं किया गया।

जहां तक टीम के प्रदर्शन की बात है तो कोच राहुल द्रविड़ गंभीर व्यक्ति है। विराट और रोहित दोनों ही उनका सम्मान करते हैं इसलिए बात और बिगड़ने की आशंका नहीं हैं जहां तक इस विवाद की परिणति का प्रश्न है तो बहुत कुछ टीम और कप्तान के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा यदि विराट कोहली का प्रदर्शन सफलता दिलाता है तो मामला रफा दफा होने की ज़्यादा संभावना रहेगी, लेकिन अगर भारत को विराट के प्रदर्शन से कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती तो बहुत संभावना है कि रोहित शर्मा तीनों प्रारूपों में कप्तान नज़र आएं। ❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

हो गई है कि अदालतों के लगातार टोकने और निर्देशित करने के बावजूद सरकारी एजेंसियों सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अवैध रेहड़ी पटरी वालों से दिल्ली के तमाम बाज़ारों में खरीदारी करने वाले और दुकानदार खासे परेशान हैं। इनके कारण बाज़ारों में चलना तक मुश्किल हो गया हैं निगमों ने हर बाज़ार में रेहड़ी पटरी वालों को बैठने की अनुमति दे रखी है लेकिन अधिकृत रेहड़ी पटरी वालों की आड़ में निगम अधिकासरियों कर्मचारियों की मिलीभगत से कई गुना अवैध रेहड़ी पटरी वालों ने बाज़ारों में कब्ज़ा कर रखा है, जिस पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, निगम भी बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी वालों को बाज़ारों में बैठने की अनुमति देते जा रहे हैं जबकि बाज़ारों में जगह नहीं है। ऐसे में यह आवश्यक है कि रेहड़ी पटरी वालों को सोच समझकर अनुमति दी जाए या उनके लिए अलग स्थान नियत किया जाए।

शेष.... भारतीय दुनिया का....

के बजाय पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सामूहिक सूचियां जारी करें और चुनाव परिणाम आने के बाद जीते हुए उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव क्षेत्र सौंप दें। इसके कारण मतदाता अपना वोट अपनी जाति के उम्मीदवार की बजाय उसकी पार्टी की विचार धारा और नीति को देंगे। जर्मनी में इसे सानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था कुछ ऐसी है कि पूरे पांच वर्ष में सिर्फ एक बार ही जनता को लगता है कि वह मालिक है और नेता उसके सेवक हैं। वोट के लिए नेता कोई भी पैंतरा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुने जाने के बाद उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। उसे क़ायम करने या लोकतंत्र को निरंतर जीवंत रखने के लिए ज़रूरी है कि स्विटजरलैंड की तरह भारत में जन प्रतिनिधियों की वापसी (रिकॉल) और क़ानूनों पर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) का प्रावधान हो। ❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : 19 Dec.2021 Posting Days : MON. - TUE. at N.D.P.S.O. New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

•हादसे का सबक़ •अनुपस्थित जनप्रतिनिधि •दिल्ली: निराशाजनक स्थिति

हादसे का सबक़

तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ हेलिकॉप्टर हादसा न सिर्फ स्तब्धकारी, बल्कि गंभीर चिंता का विषय है। उस हेलिकॉप्टर में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानि सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और उनकी सुरक्षा में तैनात लोग सफर कर रहे थे। चालक दल समेत कुल चौदह लोग उसमें सवार थे। जनरल रावत वेलिंगटन की रक्षा अकादमी में भाषण देने गए थे। दिलली से सुलूर तक वायुसेना के विमान से गए और वहां से हेलिकॉप्टर में वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में हेलिकाप्टर में वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में हेलिकाप्टर रहस्यमय ढंग से ध्वस्त हो गया। ख़राब मौसम इसकी वजह बताई जा रही है। पर इसके असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं कि एमआई श्रृंखला का यह हेलिकॉप्टर आख़िर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। सेना इस हेलिकॉप्टर को बहुत भरोसेमंद मानती हैं। इसमें दो इंजन लगे होते हैं। किन्ही परिस्थितियों में एक इंजन में ख़राबी आने के बाद दूसरा इंजन स्वत: काम करना शुरू कर देता है। इस तरह इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना न्यून रहती है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं, जिनके ज़रिए बहत सारी सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। ख़राब मौसम, बर्फबारी आदि में भी यह हेलिकॉप्टर सक्षमता से उड़ान भर और उतर सकता है। बताते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक में भी सेना ने इसी श्रृंखला के हेलिकॉप्टरों का उपयोग किया था, जिनके ज़रिए पाकिस्तान सरहद में साठ सैनिकों को उतारा गया था। यह ऊंचाई वाले स्थानों पर भी कुशलता से उड़ान भर सकता है।

हालांकि यह कोई पहला विमान हादसा नहीं था, पहले भी कई नामचीन लोग ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं, पर पिछले करीब तीस सालों में सेना के किसी बड़े अधिकारी का विमान इस तरह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। इसलिए भी इस हादसे को लेकर तरह-तरह के क़यास लगाए जा रहे हैं। जनरल रावत चूंकि भारतीय सेना विवादों सहित रक्षा परियोजनाओं की रूपरेखा पर उनकी नज़र रहती थी, इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे विमान की तैनाती नहीं की जा सकती थी, जिसे लेकर किसी भी प्रकार की आशंका हो। सेना का सर्वश्रेष्ठ हेलिकॉप्टर उनकी सेवा में तैनात था। फिर चूक कहां हुई कि ऐसा हादसा हो गया। इससे सेना की तैयारियों पर भी प्रश्न चिह्न लगता है। हालांकि इस घटना की गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर रक्षामंत्री सदन को अवगत करा चुके हैं। मगर फिलहाल यह सवाल भी अपनी जगह है कि इतने महत्वपूर्ण पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति का विमान इतना असुरक्षित कैसे साबित हुआ? सरकार के ज़िम्मेदार पदों का निर्वाह कर रहे अति विशिष्ट लोगों की यात्रा आदि के लिए जिन वाहनों और विमानों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर पूरी सावधानी के साथ जांचा परखा जाता है। उनके चालक दल में भी सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं। निजी और किराए पर लिए गए विमानों के मामले में तो फिर भी लापरवाही की आशंका हो सकती है, पर सीडीएस जैसे अति विशिष्ट व्यक्ति के विमान को लेकर किसी भी प्रकार की असावधानी अक्षम्य होती है। अगर इसके पीछे किसी प्रकार की असावधानी या साज़िश थी, जैसा कि कई लोग क़यास लगा रहे हैं, तो फिर यह ज़्यादा चिंता का विषय है। इस लिहाज़ से दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं माने जा सकते। इस हादसे से सबक़ लेते हुए शिष्टि लोगों के सुरक्षा कवच को और मज़बूत बनाने की ज़रूरत है।

अनुपस्थित जनप्रतिनिधि

बीते शीतकालीन संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने सदन में उपस्थिति के मसले पर भले भाजपा के सांसदों को सलाह दी, लेकिन उनकी बातें सभी दलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के लिए अहम मानी जानी चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य के तौर पर चुने जाने के बाद बहुत सारे सदस्य संबंधित सदन में नियमित तौर पर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी नहीं समझते। शायद ही कभी ऐसा होता हो जब सदन में सभी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित होती हो। ऐसे मौक़े आम होते हैं, जब सदन में बहुत कम सदस्य मौजूद होते हैं और इस बीच वहां कई ज़रूरी काम निपटाए जाते हैं। ज़रूरत के संदर्भ में छुट्टी पर होने या अपने क्षेत्र में कोई अनिवार्य काम निपटाने की वजह से अनुपस्थिति होने के पीछे एक तर्क है, लेकिन बिना किसी महत्वपूर्ण वजह से ग़ैर हाजिर होना अगर एक प्रवृत्ति बनती है तो यह न सिर्फ संसद के कामकाज में सभी पक्षों की भागीदारी को कमज़ोर करेगा, बल्कि इसे जनता के नुमाईन्दों के अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के तौर पर भी देखा जा सकता है। मुश्किल से हासिल की गई सदस्यता के बाद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का ख़ामियाज़ा आख़िरकार जनता को उठाना पड़ता है।

> **हमारे देश की राजनीतिक सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनज़र देखें तो यह ज़रूरी है कि संसद की कार्यवाही और वहां तय होने वाले नियम कायदों, बनने वाले कानूनों में ज़रूरी विविधता की झलक मौजूद रहनी चाहिए। अगर कोई विधेयक बिना बहस के पारित होता है तो संभव है कि भविष्य में उसके एकपक्षीय होने या संबंधित समुदाय या वर्ग का पक्ष मौजूद नहीं होने की शिकायत उभरे।**

प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों के बहाने एक तरह से सदन से बेवजह अनुपस्थित रहने की इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी की है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने सांसदों की ग़ैर हाज़िरी को जिस तरह गंभीरता से लिया, उसकी अपनी अहमियत है। इसके लिए उन्होंने साफ लहजे में हिदायत दी कि वे खुद में बदलाव जाएं, नहीं तो बदलाव वैसे ही हो जाता है। प्रधानमंत्री की इस बात में ज़रूरी संदेश छिपे हो सकते हैं, मगर इतना साफ है कि अगर सांसद अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं होते हैं तो लोकतंत्र में जनता ऐसे नेताओं का भविष्य तय करती है। सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सांसदों को यह अलग से बताए जाने की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए कि सदन में उनकी मौजूदगी उनका दायित्व है। इस ज़िम्मेदारी को उन्हें खुद क्यों नहीं महसूस करना चाहिए? इसलिए प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी का संदर्भ भी समझा जा सकता है कि बच्चों को बार बार टोका जाता है तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। ज़ाहिर है, यह सांसदों के लिए थोड़ी कड़वी घुट्टी है मगर उनकी कमियों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश भी है।

दरअसल, वह महत्वपूर्ण विधेयकों के सूचिबद्ध होने का मामला हो या अन्य ज़रूरी समकालीन मुद्दों पर विचार विमर्श या बहस का, अनेक मौक़ों पर देखा जाता है कि बहुत कम सांसदों की उपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलती रहती है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर अलग-अलग पक्षों के साथ विचार विमर्श नहीं हो पाता है। जबकि हमारे देश की राजनीतिक सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनज़र देखें तो यह ज़रूरी है कि संसद की कार्यवाही और वहां तय होने वाले नियम कायदों, बनने वाले कानूनों में ज़रूरी विविधता की झलक मौजूद रहनी चाहिए। अगर कोई विधेयक बिना बहस के पारित होता है तो संभव है कि भविष्य में उसके एकपक्षीय होने या संबंधित समुदाय या वर्ग का पक्ष मौजूद नहीं होने की शिकायत उभरे। इसके अलावा, सदन के संचालित होने का जो दैनिक ख़र्च आता है, उसका बोझ आख़िरकार जनता को उठाना पड़ता है। फिर जिस केन्द्र से देश को चलाने के लिए नीतिगत फैसले होते हों, उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी यों भी एक ज़रूरी दायित्व है। सदन का काम मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों के ज़रिए ही पूरा होता है, इसलिए इसकी अहमियत भी समझी जानी चाहिए।

निराशाजनक स्थिति

दिल्ली के बाज़ारों में अवैध रूप से कब्ज़ा जमाए बैठे रेहड़ी पटरी वालों को लेकर हाईकोर्ट का सख़्त रुख़ सर्वथा उचित है। अदालत ने इस मामले में बार-बार दिए निर्देशों पर कोई काम न करने को लेकर दिल्ली सरकार और निगमों को एक बार फिर आड़े हाथ लिया हैं हाईकोर्ट को इस बार यहां तक कहना पड़ा है कि यदि सरकारी एजेंसियां उसकी बात समझ नहीं पा रही है तो वे सामने आकर बैठें और आमने-सामने बात हो। पीठ ने तीन निगमों के आयुक्तों के साथ ही दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों समेत सभी पक्षकारों को बैठक के लिए बुलाया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत को किसी ऐसे विषय पर सरकारी एजेंसियों को लगातार कहना पड़ रहा है, जिन पर इन एजेंसियों को खुद-ब-खुद काम करना चाहिए। एजेंसियां अपना दायित्व पूरा नहीं करतीं और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़तीं रहती हैं। स्थिति इस हद तक गंभीर

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173